संयम ◆ संस्कार ◆ संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-22 अंक- 221
पृष्ठ 8
शुक्रवार
01 मई 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित | Email : shaharsamta@gmail.com | Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- गर्मियों में सुबह-सुबह चबा...
विचार- लोकतंत्र पर हावी चुनावतंत्र
खेल- रियान पराग पर बीसीसीआई...

यूपी विधानसभा सत्रः महिला आरक्षण को लेकर बरसे मुख्यमंत्री योगी, कहा-

विपक्ष महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित

लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग जन्मजात महिला विरोधी हैं, वही आज हंगामा कर रहे हैं। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल प्रदेश की जनता भली–भांति याद रखती है। उस दौर में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई, जो उनके पुराने कार्यकाल की वास्तविकता को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा के पास समर्थन करने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस दोनों ही

महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं और नारी के अधिकारों पर डाका डालने का काम करती रही हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें नैतिक साहस है तो वे सदन में चर्चा में भाग लें और बताएं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध क्यों किया। उन्होंने आगे कहा कि सपा और कांग्रेस को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने अपने निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में भी विपक्ष से माफी की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए इस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उनके इस बयान के बाद सदन में माहौल गरमा गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह मुद्दा पूरे देश व प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय पर सदन में चर्चा कराई जा सकती है और अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग करते हुए इस विषय पर चर्चा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है और विपक्ष पहले से ही उतावला दिखाई दे रहा है।

दुष्कर्म पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने संबंधी कानून में संशोधन पर विचार करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाले अपने आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने वाली एम्स की याचिका पर बृहस्पतिवार को कड़ी आपत्ति जतायी और केंद्र सरकार से बलात्कार पीड़िताओं को 20 सप्ताह से अधिक अवधि के बाद भी अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि जब गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ हो, तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि कानून को प्रासंगिक और बदलते समय के अनुरूप होना चाहिए। ब्श्प्र सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह बच्ची से बलात्कार का मामला है और यदि गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई, तो पीड़िता को जीवनभर मानसिक आघात और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि

मां को स्थायी विकलांगता का खतरा नहीं है, तो गर्भ समापन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को निर्देश दिया कि वह पीड़िता के माता–पिता को इस मामले में परामर्श दे और स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय पीड़ित किशोरी का ही होना चाहिए। पीठ ने कहा, श्देश में गोद लेने के लिए बहुत से बच्चे हैं। हमारे यहां सहानुभूति की कमी नहीं है३... सड़कों पर कई परित्यक्त और लावारिस बच्चे हैं, यहां तक कि इस पर माफिया भी सक्रिय हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह 15 साल की लड़की का अनचाहा गर्भ है। पीठ ने कहा, 'यह एक उपचारात्मक याचिका बनतंजपअम चमजपजपवद है। किसी पर अनचाहा गर्भ नहीं थोपा जा सकता। सोचिए कि वह एक बच्ची है, जिसे इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनाना चाहते हैं। उसने जो पीड़ा और अपमान सहा है, उसकी कल्पना कीजिए। एम्स की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि गर्भ समापन संभव नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चा जीवित जन्म ले सकता है, जिसमें गंभीर विकृतियां होंगी। नाबालिग मां को जीवनभर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं तथा वह भविष्य में मां नहीं बन पाएगी। इस बच्चे को गोद दिया जा सकता है।

राजगढ़ में बारातियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 26 घायल

भोपाल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी समारोह में जा रही बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बस मुरैना से उज्जैन जा रही थी। इसी दौरान ब्यावरा शहर के पास कचरी गांव के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस सड़क किनारे पलट गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस में मुरैना के तोमर परिवार के करीब 45 लोग सवार थे, जो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यात्री एक–दूसरे से टकराकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा सभी घायलों को ब्यावरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 26 घायलों का इलाज शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आठ घायलों की हालत गंभीर है। उन्हें सिर, सीने और रीढ़ में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। घायलों में सात महिलाएं और चार बच्चे भी शामिल हैं। इनमें एक पांच वर्षीय बच्चा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद मुरैना और उज्जैन दोनों परिवारों में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तेजस्वी का सरकार पर बड़ा हमला, 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री, फिर भी दिशाहीन है बिहार सरकार

पटना,एजेंसी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छह महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार से कई सवाल पूछे और कहा कि बिहार

विधानसभा चुनाव के बाद छह महीने के भीतर राज्य ने दो मुख्यमंत्री देख लिए हैं और सरकार के कार्यकाल का पहले साल का 46.03 प्रतिशत समय व्यर्थ हो चुका है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि लगभग 50: समय बीत जाने के बावजूद सरकार की प्राथमिकताएं और नीतियां तय नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि अधूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना विमर्श तथा विचार के निर्णय लिए जा रहे हैं। राजद नेता ने दावा किया कि सत्ता के लोभ में राजग नेताओं ने नैतिकता और लोकलाज की मर्यादाएं त्याग दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में पांच बार तथा 12 वर्षों में 10 बार सरकार का गठन और पुनर्गठन हुआ है। यादव ने आरोप लगाया कि बार–बार नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता और अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे बिहार दिशाहीन हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य आज बेलगाम नौकरशाही, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कमजोर कानून–व्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। राजद नेता ने दावा किया कि नयी सरकार के गठन के छह महीने में ही प्रदेशवासी उदासीन हो चुके हैं और बिहार के युवा, महिला, छात्र, किसान, कर्मचारी तथा व्यापारी अब सरकार से निराश हैं।

राजनाथ सिंह बोले-

ऑपरेशन सिंदूर भारत की मर्जी से रुका

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी इच्छा और शर्तों पर रोकने का फैसला किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय देश लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था और किसी भी परिस्थिति से निपटने की क्षमता रखता था। दिल्ली में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति अब जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवादी हमलों पर केवल कूटनीतिक बयान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमले किए गए थे। हमने यह ऑपरेशन क्षमता की कमी के कारण नहीं रोका, बल्कि इसे अपनी शर्तों पर स्वेच्छा से रोका गया था। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा भय बिन होय न प्रीति यानी बिना भय के प्रेम संभव नहीं है। यही प्रतिरोध का मूल सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी यह बात लागू होती है कि मजबूत प्रतिरोध ही शांति और स्थिरता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस सिद्धांत का वास्तविक उदाहरण है, जिसने दुनिया को भारत की नई रणनीतिक क्षमता का संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की सैन्य क्षमता लगातार मजबूत हुई है और जरूरत पड़ने पर तेजी से बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी प्रकार की परमाणु धमकी से प्रभावित नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने बताया कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर मात्र 72 घंटे में पूरा हुआ हो, लेकिन इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने लगातार आतंकवाद का समर्थन किया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही समय में आजादी मिली थी। आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। वहीं, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बन गया है। भारत का सैन्य औद्योगिक परिसर युद्धकाल में भी तेजी से आपूर्ति के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकवाद केवल ऑपरेशनल नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर भी फैलता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की राजनीतिक और वैचारिक जड़ें ही उसकी असली ताकत हैं और इन्हें खत्म करना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत की सैन्य ताकत में उसकी सर्ज क्षमता और स्टोरेज क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही स्वदेशी हथियारों की बढ़ती विश्वसनीयता ने भारत की प्रतिरोध क्षमता को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यही सभी तत्व मिलकर भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं।

मदरसों की जांच पर हाईकोर्ट सख्त

एनएचआरसी को लगाई फटकार, पूछा- किस अधिकार से हो रही है ऐसी कार्रवाई

नयी दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि आयोग उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि अन्य गंभीर मानवाधिकार मुद्दों पर उसकी सक्रियता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए गए हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच पर रोक लगी हुई है और यह जरूरी है कि जांच पूरी होने दी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रियंक कानूनगो ने हाई कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायालय ने एक मामले में यह भी कहा था कि आयोग कथित लिंचिंग जैसे मामलों में स्वतः संज्ञान नहीं लेता, जबकि मदरसों से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखा रहा है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग को जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

शहर समता विचार मंच द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सफलतापूर्वक सम्पन्न

प्रयागराज। शहर समता विचार के तत्वावधान में आयोजित गूगल मीट द्वारा काव्य गोष्ठी रचना सक्सेना की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस काव्यगोष्ठी में उमेश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। काव्यगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति साधना शुक्ला द्वारा। काव्य गोष्ठी का संयोजन एवं संचालन उमा मिश्रा प्रीति ने किया। इस

काव्य गोष्ठी में अफ़रोज़अजीज,अनीता दुबे, शशि जायसवाल, डॉ कुमकुम शुक्ला अर्चना झा, साधना खरे, रेणुका पटेल, श्रद्धा श्रीवास्तव, नीता शर्मा,संतोष मिश्रा। रचनाकार बहनों ने सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति द्वारा आयोजन में चार चांद लगा दिये धन्यवाद ज्ञापन उमा मिश्रा प्रीति ने किया।

तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की साझेदारी वाले गठबंधनों को मिलेगा बहुमत : खरगे

नयी दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी की साझेदारी वाले गठबंधनों के स्पष्ट बहुमत हासिल करने की बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि असम में नौ अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को श्एग्जिट पोलश के अनुमान से अधिक सीटें मिलेंगी। खरगे ने कहा कि पुडुचेरी में कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में लड़ाई पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के तहत मतगणना चार मई को होगी। खरगे ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा, श्कुछ जगहों पर एग्जिट पोल के नतीजे स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन कुछ परिणामों ने भ्रम की स्थिति पैदा की है। मेरा मानना है कि तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मैंने वहां के लोगों से बात की है। इसी तरह केरल में हमारे लोगों ने बताया है कि कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा, एग्जिट पोल में, असम में हमें अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं दी गई हैं लेकिन मुझे भरोसा है कि हमें उनसे अधिक सीटें मिलेंगी। पुडुचेरी में हमने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ी है। वहां भी हमें उम्मीदें हैं। यह कड़ा मुकाबला रहा है, कुछ दिन इंतजार करते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल और आंतरिक सूचना के अनुसार मुकाबला कड़ा रहा है। खरगे ने कहा, ष्हमारी जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस आगे है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने केंद्रीय बलों की तैनाती के जरिए दमन करने और डराने–धमकाने की कोशिश की, ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी जा सके। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए, पश्चिम बंगाल में हमारी शुरू से ही लड़ाई रही है। हमने वहां पहली बार अकेले चुनाव लड़ा है। हमारी लड़ाई पार्टी के हित और उसके विस्तार के लिए रही है। खरगे ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनावों के

नतीजे पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। उन्होंने कहा, अभी तीन दिन बाकी हैं। अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन इंतजार करें, तस्वीर साफ हो जाएगी। बुधवार को जारी कई एग्जिट पोल में असम में भाजपा की प्रचंड जीत और पश्चिम बंगाल में उसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिखायी गई है, जबकि तमिलनाडु में द्रमुक के सत्ता में बने रहने तथा केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ की 10 साल बाद वापसी का अनुमान जताया गया है।

प्रयागराज–दादरी स्पेशल के बढ़ाए गए फेरे, 31 मई तक चलेगी ट्रेन

प्रयागराज। प्रयागराज से नोएडा जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने दादरी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। पहले इस ट्रेन का संचालन 30 अप्रैल तक होना था लेकिन अब यह ट्रेन 2 मई से 31 मई तक नियमित रूप से चलेगी।

प्रयागराज से नोएडा जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने दादरी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। पहले इस ट्रेन का संचालन 30 अप्रैल तक होना था लेकिन अब यह ट्रेन 2 मई से 31 मई तक नियमित रूप से चलेगी।

हालांकि ट्रेन के दादरी पहुंचने के समय में बदलाव किया गया

है। अभी यह ट्रेन सुबह 5रू15 बजे दादरी पहुंच रही है लेकिन तीन मई से दादरी पहुंचने का समय सुबह 7रू15 बजे रहेगा।

इसके अलावा अब इसका संचालन सूबेदारगंज की जगह प्रयागराज जंक्शन से होगा। गाड़ी संख्या 02417 रात 8रू00 बजे सूबेदारगंज स्टेशन से प्रस्थान करेगी। सिराथू, फतेहपुर, गोविंदपुरी, फफूंद, इटावा, शिकोहाबाद, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा रुकते हुए ट्रेन अगले दिन सुबह 7रू15 बजे दादरी पहुंचेगी।

वापसी में 02418 का संचालन दादरी से रात 10रू15 बजे होगा। अगले दिन सुबह 9रू00 बजे ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाएगी। अभी यह ट्रेन दादरी से सुबह 7रू15 बजे चलकर शाम 6रू05 बजे सूबेदारगंज पहुंच रही है। रात में दादरी से प्रस्थान करने की वजह से जिन यात्रियों को प्रयागराज एक्सप्रेस या हमसफर में जगह नहीं मिल रही है, वह दादरी स्पेशल से प्रयागराज जंक्शन पहुंच सकते हैं।

कुंभ में मंथन से निकला था गंगा एक्सप्रेसवे अब यूपी की लाइफलाइन बनकर दौड़ेगा

प्रयागराज। सूबे के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे महज एक मार्ग नहीं, बल्कि आस्था, आधुनिकता और विकास के मिलन का वो अद्भुत परिणाम है, जिसकी नींव पवित्र त्रिवेणी के तट पर रखी गई थी।

सूबे के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे महज एक मार्ग नहीं, बल्कि आस्था, आधुनिकता और विकास के मिलन का वो अद्भुत परिणाम है, जिसकी नींव पवित्र त्रिवेणी के तट पर रखी गई थी। वर्ष–2019 के कुंभ में जब पूरी दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम की रेती पर कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक कर एक ऐसा संकल्प लिया था, जिसने भविष्य के उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। कैबिनेट की बैठक में ही यूपी के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा गया था।

वह तारीख थी 29 जनवरी 2019। संगम तीरे मेला प्राधिकरण के कार्यालय में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्वतंत्र देव सिंह और सिद्धार्थ नाथ सिंह समेत पूरी यूपी कैबिनेट ने प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। उक्त बैठक में स्थानीय विधायक भी शामिल हुए थे। बैठक में मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ।

इसके बाद इस महापरियोजना का औपचारिक आगाज 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर की धरती से शिलान्यास करके किया था। हालांकि, प्रशासन का लक्ष्य इसे महाकुंभ–2025 से पहले पूरी तरह संचालित करने का था, लेकिन जमीन अधिग्रहण की कुछ पेचीदा कानूनी अड़चनों और तकनीकी चुनौतियों के कारण परियोजना में करीब एक साल का विलंब हुआ।

इसके बावजूद साढ़े चार साल से भी कम के रिकॉर्ड समय में उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, जो राज्य के पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। विधायक दीपक पटेल का कहना है कि कुंभ में मंथन से निकला विकास का यह अमृत अब यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला है।

इस तरह 2019 के कुंभ ने वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया था, ठीक उसी तरह गंगा एक्सप्रेसवे अब औद्योगिक गलियारों और रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोलने जा रहा है।

योगी कैबिनेट की बैठक में शहर उत्तरी का विधायक होने के नाते मैं भी शामिल हुआ था। हम सभी लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को पारित किया। यह परियोजना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक संकल्प एक साथ मिलते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे जैसी युग परिवर्तनकारी संरचनाएं जन्म लेती हैं। – हर्षवर्धन बाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी विधानसभा

हत्या में ससुर को मिली सजा–ए– मौत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट ने कहा– यह दुर्लभतम मामला

प्रयागराज। आगरा के चर्चित सुशीलनगर दोहरा हत्याकांड में मृतका के ससुर, पति और देवर को मिली फांसी की सजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। चचेरे भाई संग अवैध संबंध के शक में बहू व उसके भाई की हत्या में दोषी पाए गए ससुर मदन सिंह की सजा–ए–मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आगरा के चर्चित सुशीलनगर दोहरा हत्याकांड में मृतका के ससुर, पति और देवर को मिली फांसी की सजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। चचेरे भाई संग अवैध संबंध के शक में बहू व उसके भाई की हत्या में दोषी पाए गए ससुर मदन सिंह की सजा–ए–मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने सत्र अदालत आगरा को ओर से मृत्युदंड को पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ का संज्ञान लेते हुए दिया है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को दो महीने में मामले की फाइल तैयार करने व 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। मामला आगरा के इतिमद–उद–दौला थाना क्षेत्र का है। सुशीलनगर में 27 मई, 2022 को गौरव ने अपने भाई अभिषेक और पिता मदन सिंह के साथ मिलकर पत्नी पूजा और चचेरे भाई शिवम की हत्या कर दी थी। उसको शक था कि पूजा और शिवम के बीच अवैध संबंध हैं। इस वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

आगरा की सत्र अदालत ने 25 मार्च को सुनाए अपने फैसले में पिता मदन सिंह और उसके दो बेटों गौरव व अभिषेक को फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए टिप्पणी की थी कि एक पिता को अपने बेटों को रोकने के बजाय अपराध में शामिल होना क्रूरता की पराकाष्ठा है। दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसे मृतका पूजा के माता–पिता को देने का आदेश था।

एसएससी जीडी भर्ती 2026 में मेडिकल नियमों में बड़ा बदलाव, अब बीएमआई होगा योग्यता का मानक

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल भर्ती–2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एसएसएफ और असम राइफल्स में चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल भर्ती–2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एसएसएफ और असम राइफल्स में चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों की छंटनी प्रक्रिया में ढील दी गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड केवल अभ्यर्थी की लंबाई, वजन और सीने की माप को आधिकारिक तौर पर दर्ज करेगा। इस प्रारंभिक चरण में अब मेडिकल ऑफिसर शामिल नहीं होंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और त्वरित हो जाएगी। उम्मीदवार के वजन का अंतिम निर्धारण विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के दौरान की जाएगी। इस चरण में मेडिकल ऑफिसर स्वयं उम्मीदवार का वजन दोबारा मापेंगे और स्वास्थ्य मानकों के आधार पर उनकी फिटनेस का निर्णय लेंगे। चिकित्सा परीक्षण के दौरान, मेडिकल ऑफिसर शारीरिक मानक परीक्षण बोर्ड पहले से दर्ज की गई लंबाई और सीने की माप को ही आधार मानेंगे। वहीं वजन और अन्य स्वास्थ्य मानकों की गहन जांच की जाएगी।

उम्मीदवारों की फिटनेस का आकलन अब बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के आधार पर किया जाएगा। जिसकी सामान्य सीमा 18 से 25 निर्धारित की गई है। 18 से कम बीएमआई वाले अभ्यर्थियों को अंडरवेट तथा 25 से अधिक बीएमआई वालों को ओवरवेट मानकर अयोग्य घोषित किया जाएगा।

संविदा समाप्ति के बाद पद पर कायम रहने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यकाल खत्म होने के बाद संविदाकर्मी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। दोबारा नियुक्ति के लिए वह नए सिरे से प्रार्थना पत्र दे सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यकाल खत्म होने के बाद संविदाकर्मी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। दोबारा नियुक्ति के लिए वह नए सिरे से प्रार्थना पत्र दे सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने पॉलिटेक्निक फतेहपुर में प्रभारी अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर तैनात रहे कर्नल विभाई मानसिंह की याचिका खारिज कर दी।

मामले के मुताबिक, याची अगस्त 2025 में 31 मार्च 2026 तक के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। कार्यकाल समाप्त होने पर विभाग ने उन्हें पद छोड़ने का नोटिस दिया। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दी कि नियमानुसार संविदा अवधि दो वर्ष की होनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने कहा कि जब याची ने 31 मार्च तक की नियुक्ति की शर्तों को बिना विरोध स्वीकार किया था, तो अब वह कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कार्यकाल पूरा होने पर विभाग का नोटिस देना सही है। हालांकि, कोर्ट ने याची को यह छूट दी है कि यदि वे चाहें तो भविष्य में दोबारा संविदा नियुक्ति के लिए अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

बिना शट डाउन लिए लाइनमैन को खंभे पर चढ़ाया, 11 हजार लाइन की करंट से युवक की मौत

प्रयागराज। कमल्दीपुर गांव में मंगलवार की देर रात छिबैया ग्रामीण फीडर पर चलती लाइन पर सेक्शन का जंफर खोलने के लिए खंभे पर चढ़े लाइनमैन 27 वर्षीय रामू कुशवाहा पुत्र गया प्रसाद कुशवाहा की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।

कमल्दीपुर गांव में मंगलवार की देर रात छिबैया ग्रामीण फीडर पर चलती लाइन पर सेक्शन का जंफर खोलने के लिए खंभे पर चढ़े लाइनमैन 27 वर्षीय रामू कुशवाहा पुत्र गया प्रसाद कुशवाहा की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। आरोप है कि चलती लाइन पर पीडीए की त्रिवेणीपुरम कॉलोनी के बिजली उपकेंद्र पर तैनात सरकारी लाइनमैन रमेश ने उसे खंभे पर चढ़ाया था।

मंगलवार की रात करीब 11 बजे से ही त्रिवेणीपुरम कॉलोनी के बिजली उपकेंद्र से आपूर्ति प्रभावित थी। इस दौरान चमनगंज में एक बरातघर के पास केबल में आग लग गई। ऐसे में त्रिवेणीपुरम के साथ ही छिबैया जाने वाला देहात का फीडर भी ट्रिप कर गया। किसी तरह रात एक बजे सरस्वती फीडर को ठीक किया गया। कुछ देर बाद पता चला कि छिबैया फीडर से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है।

आरोप है कि इसी दौरान त्रिवेणीपुरम बिजली उपकेंद्र पर तैनात सरकारी लाइनमैन रमेश ने अपने साथ काम करने वाले निजी लाइनमैन रामू कुशवाहा को कमल्दीपुर गांव के पास चलती लाइन पर सेक्शन का जंफर खोलने के लिए खंभे पर चढ़ा दिया। जैसे ही रामू खंभे पर चढ़ा कि 11 हजार की लाइन की चपेट में आने से वह गिर गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी अफसरों के साथ ही झूंसी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ झूंसी महेश मिश्र ने बताया कि मृतक रामू की करीब पांच साल मंगीता कुशवाहा से विवाह हुआ था। दो साल की बेटी दीपा है। एसओ झूंसी महेश मिश्र ने बताया कि आरोपी सरकारी लाइनमैन रमेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आधी रात पति को बुलाकर ले गया था आरोपी

रामू कुशवाहा की पत्नी मंगीता का आरोप है कि आधी रात को सरकारी लाइनमैन रमेश उसके घर आए और पति को जबरन अपने साथ बिजली की फाल्ट दूर करने के लिए ले गए। पत्नी मंगीता की तहरीर के मुताबिक, पहले सरकारी लाइनमैन रमेश ने उसके पति को आधी रात को कई बार फोन लगाया। जब रामू ने फोन नहीं उठाया तो रमेश खुद उसके घर पहुंच गया। कहा कि मौके पर चलकर तुमको केवल सीढ़ी पकड़ना है। आरोप है कि रमेश ने उसके पति रामू को चलती लाइन में बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। हादसे के वक्त मौके पर रवि मौर्य और अकील भी मौजूद थे।

पत्नी को बुलाओ वर्ना कूद जाऊंगा, छिवकी स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा

प्रयागराज। प्रयागराज के छिवकी स्टेशन परिसर में मंगलवार सुबह एक युवक फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग थी कि उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया जाए, अन्यथा वह कूदकर जान दे देगा। प्रयागराज के छिवकी स्टेशन परिसर में मंगलवार सुबह एक युवक फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग थी कि उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया जाए, अन्यथा वह कूदकर जान दे देगा। करीब दो घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा। घटना सुबह करीब 10.30 बजे की है। मेजा निवासी अभि सिंह अचानक तेजी से मोबाइल टावर पर चढ़ने लगा। टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर वह चिल्लाने लगा और नीचे खड़ी लोगों से पत्नी को बुलाने के लिए कहा। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने उसे युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इस बीच, अभि ने अपने ससुर का मोबाइल नंबर पुलिस को दिया। पुलिस ने फोन कर उसकी पत्नी को बुलाया। करीब 12रू30 बजे पत्नी पहुंची। उसने और पति को समझाते हुए नीचे आने की गुहार लगाई। पत्नी के आश्वासन के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। बताया जा रहा है कि युवक ने प्रेम विवाह किया था और पारिवारिक विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया।

एसपी मिलते नहीं, अधीनस्थ याचिका वापस लेने का बना रहे दबाव

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के मामले में पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पाया कि पुलिस न केवल किशोरी को तलाश करने में विफल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के मामले में पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पाया कि पुलिस न केवल किशोरी को तलाश करने में विफल रही है, बल्कि पीड़ित पिता को प्रताड़ित करने और याचिका वापस लेने के लिए डराने–धमकाने के गंभीर आरोप हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह के भीतर पीड़िता को पेश करने और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याची अकरम खान के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि याची जब भी अपनी लापता बेटी की खोजबीन के लिए एसपी के कार्यालय जाता है, उसे सुनने के बजाय कार्यालय से बाहर निकलवा देते हैं। एसपी और उनके मातहत अधिकारी उसे याचिका वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वहीं, कोर्ट ने एसपी का हलफनामा पढ़ने के बाद कहा कि ऐसा लगता है जैसे एसपी अदालत को हल्के में ले रहे हैं। हलफनामे में केवल केस डायरी के पन्नों का विवरण देकर कहानियां सुनाई गई हैं। पीड़िता को तलाश करने के ठोस प्रयास नजर नहीं आते। एसपी संभल स्वयं के हलफनामे के माध्यम से स्पष्ट करें कि याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने और याचिका वापस लेने के लिए धमकाने के आरोपों पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया गया है कि वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संभल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर यह आदेश एसपी तक पहुंचाएं। मामले की अगली सुनवाई 07 मई 2026 को निर्धारित की गई है।

मनरेगा में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार केवल सक्षम प्राधिकारी को

प्रयागराज। मनरेगा के तहत वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार केवल सक्षम प्राधिकारी को ही है। यह टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधान व अन्य पर मनरेगा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग में वार्ड सदस्य की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी ने बस्ती जिले की वार्ड सदस्य सुशीला सिंह की याचिका पर दिया है। मामला बस्ती के विकास खंड साल्तौवा गोपालपुर के ग्राम पंचायत मझौवा बैकुंठ का है, जहां की निर्वाचित वार्ड सदस्य सुशीला सिंह ने ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मनरेगा फंड के गबन का आरोप लगाया था। आरोप था कि प्रधान ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। जब मजिस्ट्रेट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया, तो याची ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एफआईआर दर्ज कराने की शक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रदान है। प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर केवल नामित अधिकारी ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकृत है। इसी के साथ कोर्ट ने दायर पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी।

गैस लीकेज से सिलिंडर में विस्फोट, महिला गंभीर रूप से झुलसी

प्रयागराज। चरवा कोतवाली के पहाड़पुर सुधवर गांव में बृहस्पतिवार सुबह चाय बनाते समय गैस लीकेज के कारण सिलिंडर में आग लग गई और तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलस गई। चरवा कोतवाली के पहाड़पुर सुधवर गांव में बृहस्पतिवार सुबह चाय बनाते समय गैस लीकेज के कारण सिलिंडर में आग लग गई और तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने उसे आनन–फानन में इलाज के लिए सीएचसी चायल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। पहाड़पुर सुधवर गांव की कलावती ने बताया कि उनके पति बुधनाथ विश्वकर्मा की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उनके दोनों बेटे बृजेश और सिप्पू दूसरे प्रांत में काम करते हैं और रिश्तेदारी में शादी होने के कारण इन दिनों घर आए हुए हैं। बृहस्पतिवार सुबह बहू सराध्या देवी रसोई में चाय बना रही थीं, तभी अचानक गैस रिसाव होने लगा और देखते ही देखते सिलिंडर में आग लग गई।

टेढ़ा हो गया लोहे का दरवाजा, उखड़ गया छत का प्लास्टर

आग लगते ही घर में अफरा–तफरी मच गई। बहू जान बचाने के लिए शोर मचाते हुए रसोई से बाहर भागी, जबकि कलावती घर का सामान निकालने के लिए कमरे में पहुंच गईं। इसी दौरान तेज धमाके के साथ सिलिंडर फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गईं। विस्फोट इतना तेज था कि रसोई में लगा लोहे का दरवाजा टेढ़ा होकर बंद हो गया। इससे कमरे की दीवार और छत का प्लास्टर उखड़ गया और दरारें पड़ गईं।

गनीमत रही कि दरवाजा बंद होने से सिलिंडर के टुकड़े कमरे के अंदर ही रह गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से घायल महिला को सीएचसी चायल पहुंचाया। सीएचसी अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि महिला भर्ती कर लिया गया है। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकलपीठ ने दारा सिंह चौहान की याचिका पर दिया। दारा सिंह चौहान के खिलाफ मऊ के मोहम्मदाबाद थाने में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी एक बैठक कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चौहान को समन जारी किया था। इसके खिलाफ दारा सिंह चौहान ने हाईकोर्ट का रुख किया और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

पिता बच्चे की अभिरक्षा किसी को भी नहीं सौंप सकता, ऐसा दृष्टिकोण कानून और नैतिकता दोनों के विरुद्ध

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि पिता अपने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है और इस निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि पिता अपने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है और इस निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसा दृष्टिकोण कानून और नैतिकता दोनों के विरुद्ध है। इसके साथ ही कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

मामले को कानून के अनुसार पुनः निर्णय के लिए एकलपीठ को वापस भेज दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने प्रयागराज के युवराज, आयुष्मान व अन्य की विशेष अपील पर दिया। मामले में याची के पिता ने बच्चों की अभिरक्षा उनकी मां को देने के बजाय अन्य व्यक्तियों को सौंप दी थी। इसे अवैध निरुद्धि बताते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी।

हालांकि, एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि पिता को अभिरक्षा स्थानांतरित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पिता भले ही नाबालिग का नैसर्गिक संरक्षक हो। लेकिन उसे यह असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी इच्छा से बच्चे की अभिरक्षा किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दे और दूसरे अभिभावक को इसे चुनौती देने से रोका जाए।

महावन तहसील में आरओ खराब, प्यासे लौटे फरियादी

मथुरा। भीषण गर्मी के बीच महावन तहसील परिसर में लगे आरओ वाटर प्लांट के खराब होने से फरियादियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर में लगा आरओ काफी समय से बंद पड़ा है, जिससे दूर–दराज से

आने वाले ग्रामीणों और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। गुरुवार को भी कई फरियादी पानी के लिए इधर–उधर भटकते नजर आए और अंततः बिना पानी पिए ही वापस लौटने को मजबूर हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द आरओ को ठीक कराना चाहिए, ताकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। तहसील में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या के समाधान को लेकर अब तक गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

नागालैंड नंबर ट्रक से 283 पेटी अवैध शराब बरामद, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

मथुरा। जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग ने थाना जैत क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा वैली के सामने चेकिंग के दौरान हरियाणा की ओर से आ रहे नागालैंड नंबर के बंद बॉडी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में लकड़ी के बड़े बॉक्सों में छुपाकर अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा था।

बरामदगी में कुल 283 पेटी शराब शामिल है, जिनमें 51 पेटी फुल बोतल, 174 पेटी हॉफ एवं 58 पेटी क्वार्टर हैं। कुल शराब की मात्रा 2526.12 बल्क लीटर बताई गई है, जो हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य थी, लेकिन इसे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। मामले में थाना जैत पर आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

3 मई को भयहरणनाथ धाम में होगा 8वाँ सामाजिक सत्याग्रह

राजस्व विभाग करेगा मन्दिर, तालाब सहित सामलाती सभी भूखंडों की पैमाइश

प्रतापगढ़। प्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरणनाथ धाम में धाम व धाम से जुड़ी सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग के साथ गत माह से जारी 8वाँ सामाजिक सत्याग्रह 3 मई 2026, दिन शनिवार को प्रबन्ध समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा।

राजस्व विभाग अपने वायदे के अनुसार इसी दिन वर्तमान राजस्व अभिलेखों में राजस्व ग्राम पूरे वैष्णव में दर्ज खतौनी सं० 493 के सभी सम्मिलित गाटों की भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। राजस्व विभाग ने सभी काश्तकारों से अपनी खतौनी की प्रति के साथ सहयोग की अपेक्षा की है। भयहरणनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान के महासचिव समाज शेखर ने बताया कि मन्दिर से जुड़े गाटों के कुल रकबे का चिन्हांकन हो चुका है, वहीं अन्य खातों– तालाब, देवस्थान व अन्य काश्तकारों की भूमि अलग–अलग चिन्हांकित की जाएगी। इस अवसर पर धाम के अध्यक्ष राज कुमार शुक्ल व कार्यवाहक अध्यक्ष लाल जी सिंह के संयोजन में सामाजिक सत्याग्रह व पैमाइश में सहभागिता तथा सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर सभी ने एसडीएम सदर द्वारा गठित 10 सदस्यीय पूरी राजस्व टीम व पर्याप्त पुलिस बल की मांग की है।

महिला आरक्षण पर नहीं चलेगी जल्दबाजी, कांग्रेस की मांग- विशेष सत्र का बढ़े समय, हो विस्तृत चर्चा

लखनऊ (संवाददाता)। महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर बुलाए जा रहे विशेष सत्र पर कांग्रेस ने सरकार की तैयारी और मंशा दोनों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्पष्ट कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर महज पांच घंटे की चर्चा पर्याप्त नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि विशेष सत्र का समय बढ़ाया जाए, ताकि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले मुद्दे पर सभी पक्ष विस्तार से अपनी बात रख सकें। उनका कहना है कि यह केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी–नारी शक्ति–के अधिकारों और भागीदारी से जुड़ा विषय है। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर जल्दबाजी न करे और पूरे दिन से भी अधिक समय देकर गंभीर और सार्थक चर्चा सुनिश्चित करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला आरक्षण को लेकर उतनी गंभीर नहीं दिख रही, जितनी होनी चाहिए। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन इस पर ठोस और व्यापक बहस जरूरी है। पार्टी का मानना है कि पर्याप्त समय और गहन विचार–विमर्श के बिना इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जो बात हो रही है वह केंद्र सरकार का विषय है। इसलिए सदन में यह चर्चा नहीं होनी चाहिए।

विश्वनाथ इकाई की अप्रैल माह की काव्य गोष्ठी सम्पन्न

विश्वनाथ। सैयदा आनोवारा खातून की संजोजन एवं संचालन में और अफ़रोज़ अज़ीज़ की अध्यक्षता में गुगल मीट द्वारा शाम 7.00 बजे सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ एक दीप प्रज्ज्वन और सरस्वती की मुर्ति पर माल्यार्पण के साथ सैयदा अनोवारा खातून ने सुंदर भक्तिमय सरस्वती वंदना के प्रस्तुति की।

आज मंच पर उपस्थित थे भारत के विभिन्न प्रदेशों से कवि –कवयित्री, लेखक –लेखिका हिंदी के विद्वान तथा अध्यापक, प्राचार्य, हिंदी सेवक सेविका आदि।

मुख्य अतिथि के रुप में –जम्मू से, भाषाविद पूर्व प्राचार्य– गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नौशहरा राजौरी (सेवानिवृत्त) एवं मंत्री जम्मू– राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ,वरिष्ठ लेखक, सम्पादक, प्रकाशक, आदरणीय भारत भूषण शर्मा जी

विशिष्ट अतिथि में –राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर से सह प्राचार्य (हिंदी विभाग)आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी ।

दिल्ली से वरिष्ठ सायरा आदरणीया अफ़रोज़ अज़ीज़ जी

असम से युवा –वरिष्ठ व्याख्याता, कवि ,समीक्षक ,पर्यवेक्षक प्रक्षिशण केंद्र न्यू बंगाईगांव (पूसी रेल), आदरणीय विनय कुमार जी कवयित्री शिक्षिका मनीषा पाल जी। असम से असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तथा वर्धा समिति के प्रचार

युवा कवि एवं हिंदी सेवी, अध्यापक (प्रतापगढ़ आदर्श मॉडल हाई स्कूल) संतोष कुमार महतो जी। देहरादून से वरिष्ठ गज़लकार आदरणीय आलम मुसाफिर जी, असम से युवा कवि, हिंदी सेवक, एवं शिक्षक आदरणीय सुजीत कुमार जी ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई।

जिलाध्यक्षा सैयदा आनोवारा खातून जी भी कार्यक्रम में सहभागी रहे।

भारत भूषण शर्मा जी ने कहा कि आज इस तरह गुगल मीट के जरिए पूर्वोत्तर के साहित्यकारों से मिलकर बड़ा आह्लादित हुआ।

राजीव रंजन प्रसाद जी ने भी कहा – इस तरह गुगल मीट द्वारा आयोजित साहित्यिक मंच अति आवश्यक है क्योंकि इस के जरिए हिंदी भाषा साहित्य एवं संस्कृति को विकास में एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है ।और पूरे भारत के साहित्यकारों से साहित्यक संबंध का अवसर भी प्राप्त होता है

मंच पर सभी ने अपनी सुंदर भावपूर्ण कविता और ग़ज़ल से चार चांद लगा दिए। सभी रचनाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी।

चाहे वह अफ़रोज़ अज़ीज़ की – ष्बर्बादियों का अपनी किसी से गिला नही ष –विनय जी के – ष दुआओं में जिसे मांगा वही वरदान है बेटी ष––आलम मुसाफिर जी के –– ''दर्द के ऑसू ने लिक्खी इक कहानी बाप की '' आनुवारा खातून जी की श साथ मेरे चल रहा है गम का लश्कर किसलिए श

मनिषा पाल की – जंगली फूलो की दास्तां ष्सुजीत कुमार जी के ष ष चुनाव आया ष

कार्यक्रम के अंत में सभी साहित्यकारो के गरिमामय उपस्थित के लिए जिलाध्यक्षा सैयदा अनोवारा खातून जी को धन्यवाद ज्ञापन किया। और आगे भी इसी तरह विश्वनाथ इकाई में जुड़कर सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।

स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं का हंगामा, यमुना पार बिजलीघर पर धरना

मथुरा। यमुना पार क्षेत्र के यमुना विहार में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने बिजलीघर पर जोरदार धरना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई।

महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अनावश्यक बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त जानकारी और सहमति के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। धरने पर बैठी महिलाओं ने मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और पुराने मीटर बहाल किए जाएं। मौके पर

पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं।

प्रदर्शन में सुमन देवी, सीमा, कोमल चौधरी, अंजू, पूजा, कमलेश सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रहीं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

यूपी को मिलेगा एक और 6 लेन हाईवे

नेपाल तक होगी कनेक्टिविटी, नौ हजार दरख्तों पर चलाना पड़ेगा आरा

लखनऊ (संवाददाता)। बाराबंकी से बहराइच के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की हरी झंडी कैबिनेट से भले मिल गई लेकिन वन विभाग की अनुमति बाकी है। अक्टूबर 2026 से काम शुरू होना है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई पत्राचार के बाद भी वन विभाग से एनओसी का इंतजार है।

सचिव वन से क्लीयरेंस मिलना है। छह लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग मुस्तफाबाद से कैसरगंज होते हुए बहराइच तक जाएगा। इसमें संरक्षित वन विभाग की 70 हेक्टेयर जमीन है।वन विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के अलाइनमेंट का बदलवाना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग में नौ हजार

पेड़ आ रहे हैं, जिन्हें सड़क बनाते वक्त काटना ही पड़ेगा व कई हेक्टेअर जमीन भी जाएगी। वन विभाग अलाइनमेंट बदलवाने का प्रयास कर रहा है। एनएचएआई का तर्क है कि पीएमओ कार्यालय से अलाइनमेंट की स्वीकृति मिल चुकी है। अगर अलाइनमेंट बदलता है तो शहर के भीतर से राजमार्ग निकलेगा और सैकड़ों मकान गिराए जाएंगे, इससे प्रोजेक्ट की लागत कई सौ करोड़ बढ़ेगी। पत्राचार के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट विलंब से शुरू होने की संभावना है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दावा किया है कि अक्टूबर 2027 तक बाराबंकी से बहराइच के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाएगा। वन विभाग की एनओसी व जमीन अधिग्रहण में अगर विलंब हुआ तो प्रोजेक्ट कैसे समय से शुरू हो पाएगा? बाराबंकी से बहराइच के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–927 का निर्माण 6,969.04 करोड़ की लागत से बनना है।

यूपी विधानसभा में विशेष सत्र के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, अध्यक्ष बोले, चर्चा संभव

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में बृहस्पतिवार को लाए गए प्रस्ताव को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आपत्ति जताई और कहा कि जो विषय राज्य सरकार का नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कार्यक्रम के प्रस्ताव की जानकारी दी। इस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा, श्नियमावली कहती है कि जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो, उस पर बहस या मतदान नहीं कराया जाना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक संसद के अधिकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। पांडेय ने कहा, हम नारी सशक्तिकरण या नारी आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, हम समर्थन में हैं। लेकिन प्रस्ताव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बाधा उत्पन्न करने की बात निंदात्मक है। सवाल है कि बाधा कहां उत्पन्न की जा रही है? यह विषय कहां से आता है? इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, दुख हुआ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर नेता प्रतिपक्ष, जो स्वयं सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं, यह आपत्ति उठा रहे हैं।

आओ सीखें फूल से

उम्मीदों के साथ में, सुखन सुहानी भोर।
कलियों को मुस्कान दे, करे न कोई शोर।
करे न कोई शोर, सुगन्धित उपवन सारे।
बदल गया माहौल, सभी कुछ लगते न्यारे।
सुन लो कहें प्रदीप, द्वार खुल आशीषों के।
तम में भरें प्रकाश, हमेशा उम्मीदों के।

सबकुछ पावन है यहाँ,करके यह विश्वास।
आओ सीखें फूल से, कैसे भरें सुवास।
कैसे भरें सुवास, प्रश्न है सीधा–साधा।
समझ कली विज्ञान, उसी में उत्तर सारा।
सुन लो कहें प्रदीप, न होते हैं जो व्याकुल।
खुशबू जग में बाँट, वही पाते हैं सबकुछ।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

वनकामं के उत्तर प्रदेश की इकाई की काव्य गोष्ठी हुई सम्पन्न

कवियों ने बहाई काव्य की रसधारा

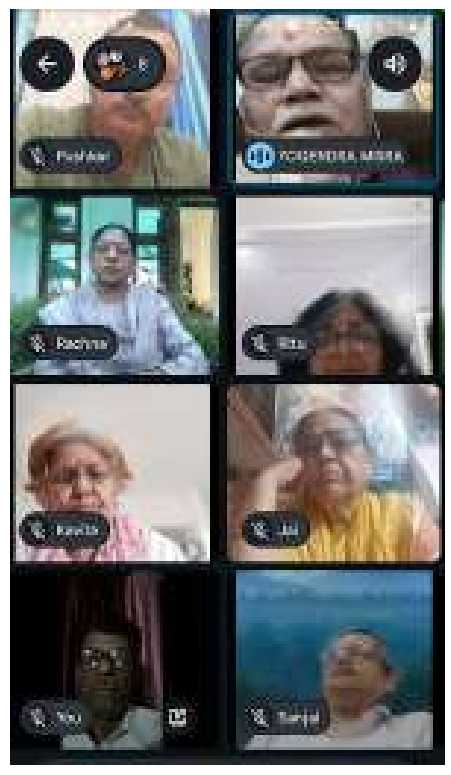

प्रयागराज। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, उत्तर प्रदेश की पूर्वी इकाई की एक मासिक ऑनलाइन काव्य गोष्ठी वनकाव्य मंच के

हरियाणा–2 इकाई की उपाध्यक्षा रितु गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई। इसमें वरिष्ठ रचनाकार जया मोहन और कविता उपाध्याय का सानिध्य रहा। इस अवसर पर सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना महिला काव्य गोष्ठी की अध्यक्षा रचना सक्सेना की वाणी वंदना से हुई। कार्यक्रम का शानदार संचालन वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच उ.प्र. इकाई के अध्यक्ष पंडित राकेश मालवीय मुस्कान ने किया। वहीं शहर के गणमान्य और लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ कवियों ने अपनी रचनाओं से पटल को गुंजायमान किया। इनमें प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि रितु गुप्ता, वनकामं के संरक्षक संजय सक्सेना, अध्यक्ष पंडित राकेश मालवीय मुस्कान, शहर समता के संपादक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार उमेश श्रीवास्तव, योगेन्द्र कुमार मिश्र विश्वबंधु, वरिष्ठ कवयित्री कविता उपाध्याय, संजय सक्सेना, रचना सक्सेना, जया मोहन, इंदु प्रकाश मिश्रा जमदग्नि, पुष्कर प्रधान, ने शानदार काव्य पाठ करके मंच में चार चाँद लगा दिया। सबने एक से बढ़कर एक रचनाएँ प्रस्तुत की। धन्यवाद व आभार ज्ञापन संजय सक्सेना ने किया।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सं0: पी आर वाइ जे-सिग-007-2026-27

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से वरि0 मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियन्ता/समन्/उत्तर मध्य रेल प्रयागराज द्वारा ई-टेन्डर के द्वारा पर्याप्त वित्तीय क्षमता एवं अनुभव सहित प्रतिष्ठित ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिये खुली निविदा, ई-निविदा में वर्णित खुलने के दिनांक को 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

निविदा नं0 : 007	अनुमानित मूल्य : 12798370.76
कार्य का विवरण : प्रयागराज मण्डल में सुनार-सोमन खण्ड के [illegible] सेक्शन में 02 नं0 गैर इन्टरलॉक समपार फाटक (समपार फाटक संख्या 28 एवं समपार फाटक संख्या 33) का इन्टरलॉकिंग।	
बिड सिक्यूरिटी : 255900	निविदा प्रपत्र का मूल्य : 0.00
कार्य समापन की अवधि : बारह माह	निविदा खुलने की तिथि : 26.05.2026
निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता : निविदा प्रपत्र www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।	
निविदा खुलने का समय, तथा स्थान : निविदा पूर्व निर्धारित तिथि 12:30 बजे या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जायेगी। अगर उस दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहे तो निविदा अगले दिन, कार्य दिवस पर खोली जायेगी। 938/26 (C)	

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

उत्तर मध्य रेलवे

ई-प्रापण निविदा सूचना संख्या : 26/16 दिनांक : 28.04.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उ0म0रे0, प्रयागराज (आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाणित इकाई) निम्नलिखित मदों के लिए ई-प्रापण निविदायें आमंत्रित करते हैं-

क्र. सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	निविदा खुलने की तिथि
1	20255024	सेट ऑफ आइटम्स फॉर 'H' टाइप टाइट लॉक कपलर	50 सेट	25.05.2026
2	20263067	IOH रिप्लेसमेंट किट फॉर VCB	81 सेट	25.05.2026
3	40261223	सिलिकॉन पावर कम्पाउंड	23738 नग	25.05.2026
4	40263015	टैम्प [illegible] फ्लैक्स [illegible] यूनिफार्म मफ्स	129553 मीटर	28.05.2026
5	60255038	हाइड्रॉलिक रि-रेलिंग उपकरण	2 सेट	21-05-2026

नोट : उपरोक्त सभी ई-प्रापण निविदाओं का पूरा विवरण IREPS वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाओं में किसी भी बदलाव/शुद्धि-पत्र के लिए कृपया इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें। समाचार-पत्र में कोई अलग से शुद्धि-पत्र/परिवर्तन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 931/26 (D)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

उत्तर मध्य रेलवे

टेण्डर सूचना संख्या-वि./ग.श.यू./प्रयागराज/ई-टेण्डर/2026/63 दिनांक 24.04.2026

ई-निविदा सूचना

उप मुख्य बिजली इंजीनियर/गति शक्ति यूनिट/उ.म.रे./प्रयागराज द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

निविदा सं.: वि.ग.श.यू.-कार्य ठेका-77-2026	
कार्य का विवरण: प्रयागराज मण्डल के इटावा स्टेशन पर आइलैंड प्लेटफॉर्म के निर्माण के कारण 25 केवी ओएचई संशोधन कार्य।	
अनुमानित लागत: ₹ 20753084.64	बिड सुरक्षा राशि ₹ 415100.00
कार्य अवधि: 12 महीना	बोली प्रणाली: एक पैकेट
निविदा बन्द होने की तिथि तथा समय: 18.05.2026, 14.00 बजे	
निविदा खुलने की तिथि तथा समय: 18.05.2026, 15.00 बजे	

नोट- 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होगा। 2. उपरोक्त निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिये कि वे अपने आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिये IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 924/26 FA

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

सम्पादकीय.....

पर्यावरण संकट की चुनौती

पिछली डेढ़ शताब्दी से, जब से औद्योगिक क्रांति ने विकास की गति तेज की और प्रकृति को जीतने की होड़ मच गई, मशीनों ने बंधक– निर्माण – शक्ति मानव के हाथ में दे दी, तब से विकास की परिभाषा भी धीरे–धीरे बदल गई। गुणात्मक जीवन के बजाय बाहुल्य को विकास माना जाने लगा। प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार का एक अंतहीन सिलसिला आरंभ हो गया। प्रकृति के दोहन से ही बाहुल्य के लिए सामान बनाए जा सकते थे, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन की शुरुआत हो गई। उपनिवेशवाद के दौर में कम मशीनी शक्ति वाले देशों पर तथाकथित विकसित देशों द्वारा कब्जे किये गए और उनके संसाधनों को बेदर्दी से नष्ट किया गया। सभ्य कहलाने वाले देशों द्वारा कमजोर देशों के मूल निवासियों को किस तरह प्रताड़ित किया, उनकी सभ्यताओं को असभ्य घोषित करके नष्ट करने का कार्य किया, वह अपने आप में घिनौना इतिहास है। इसके अवशेष अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में देखे जा सकते हैं, किन्तु यह आधुनिक सभ्यता अब अपने ही भार से भस्मासुर की तरह नष्ट होने की दिशा में बढ़ती प्रतीत हो रही है। इस सभ्यता ने अपने ही मूल पर आघात करना शुरू कर दिया है। हालांकि वैज्ञानिक समझ के विकास के चलते सब गलत दिशा को समझ भी रहे हैं, किन्तु विज्ञान का दुरूपयोग प्रकृति विनाशक शक्ति के रूप में किया जा रहा है। दुनिया के सबसे विद्वान वैज्ञानिकों को युद्ध–विज्ञान के विकास में संलग्न कर दिया गया है। निर्णय लेने वाले लोग तो आदिम क्रूर मानसिकता के ही वाहक बने हुए हैं जिनके हाथ में मशीन और विज्ञान, प्रकृति एवं प्राणी समाज के साथ मनमानी करने का हथियार बन गया है। ज्ञान, सुख और शांति का वाहक बनने के बजाय युद्ध और क्रूरता का वाहक बन गया है। इस स्थिति में श्संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमश के सातवें अधिवेशन में नैरोबी में प्रस्तुत की गई श्ग्लोबल आउटलुक 2025श रिपोर्ट पर्यावरण के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को उजागर करती है और अपने तौर–तरीकों पर मानव समाज को पुनर्विचार करके संशोधित करने की दिशा दिखलाती है। जलवायु परिवर्तन प्रकृति के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया के रूप में एक बड़े खतरे की चुनौती पेश कर रहा है। मशीनीकरण को चलाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की बड़े पैमाने पर जरूरत है वह जीवाश्म ईंधन से पैदा की जा रही है। इस उत्पादन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धुआं और जहरीली गैसें उत्सर्जित होती हैं जो हरित प्रभाव पैदा करके वायुमंडल के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि कर रही हैं। तापमान वृद्धि से पूरे जलवायु का संतुलन हिल गया है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं अनावृष्टि हो रही है। ग्लेशियर पिघल कर समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं जो आसन्न जल–संकट का कारण बनेंगे। रिपोर्ट के अनुसार श्हरित प्रभाव गैसोंश के उत्सर्जन से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान 2024 में बढ़कर 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। इस गति से वृद्धि होने पर जलवायु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो आगे बढ़ता ही जाएगा। यदि तापमान वृद्धि को रोका नहीं गया तो इसके कारण जैव–विविधता पर भी बुरा असर पड़ने वाला है, जिससे 10 लाख प्रजातियों के लुप्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। 20 से 40 प्रतिशत भूभाग वैश्विक स्तर पर अनुपजाऊ होने के कगार पर है जिससे 300 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जलवायु से जुड़ी भीषण घटनाओं के कारण जन–धन की भारी हानि हो रही है। आर्थिक रूप में वार्षिक 14,300 करोड़ डॉलर की हानि पिछले दो दशकों से हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण 2019 में स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक नुकसान 8.1 ट्रिलियन डॉलर आंका गया था, जो वैश्विक अर्थ–व्यवस्था का 6.1 प्रतिशत है। 90 लाख मौतें प्रदूषण संबंधी कारणों से हुईं। 80 हजार लाख टन प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है, जिससे गंभीर रासायनिक तत्वों से संपर्क हो रहा है और इससे 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक हानि प्रति–वर्ष हो रही है। श्नैनो प्लास्टिकश तत्व मनुष्य शरीर तक पहुंच कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अनुमान है कि यदि सन् 2040 तक तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच गई तो जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक–व्यवस्था का अपूरणीय विनाश हो सकता है। इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो सकती हैं और बेरोजगारी, गरीबी, और अस्थिरता बढ़ेगी। उपजाऊ जमीनों के नष्ट होने से भूख, विविधता–विनाश, पौष्टिक आहार की कमी, अकाल और सामाजिक असंतोष के हालात बनेंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल गंभीर प्रयास करने की जरूरत है, किन्तु जलवायु नियंत्रण समझौतों के विषय में बहुत से देश विमुखता दिखा रहे हैं। जो मान भी रहे हैं, वे भी हरित प्रभाव गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए स्व–घोषित लक्ष्य ही मानने तक सीमित रहना चाहते हैं। इस स्थिति से बाहर निकल कर कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे, खासकर हरित प्रभाव गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी। इसके लिए कार्बन–मुक्त ऊर्जा विकल्पों की ओर मुड़ना होगा।

लोकतंत्र पर हावी चुनावतंत्र

अरविंद मोहन

यह आलेख लिखे जाने तक बंगाल के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार रुक चुका है। चुनाव हर बार ज्यादा दिलचस्पी जगाते हैं, उनके नतीजों का असर सामान्य दिखने की तुलना में ज्यादा गहरा होता है लेकिन बंगाल का इस बार का चुनाव पड़ोस के असम या साथ चुनाव में उतरे तमिलनाडु और केरल से कहीं ज्यादा दूरगामी असर वाला है, इसकी विकृतियां ज्यादा बड़ी हैं। यह सब कहने का मतलब यही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद वहां जो कोई सत्ता में आए या केंद्र में बैठे बड़े लोग हों, सबको बहुत ठंडे मन से चुनाव के पूरे क्रम और अपने कामों पर भी गंभीरता से सोचना होगा और चीजें सुध ारने की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन यह भी लगता है कि अगर एक दशक तक गंभीरता से काम हो, तब शायद सुधार हो पाएगा। इसमें लोगों की मुस्तैदी भी जरूरी है। लेकिन आज चुनाव ऐसा बन चुका है कि चीजें कहां से संचालित होती हैं, कहना मुश्किल है और लोगों के पास एक बटन दबाने में विवेक दिखाने के अलावा ज्यादा कुछ बचा नहीं है। शायद उससे ही चमत्कार हो जाए। चुनावी खर्च मुद्दा नहीं रह गया है और बंगाल चुनाव में भी ज्यादा बड़ा मुद्दा हो, लगा नहीं। अदने से विधायक हुमायूं कबीर को हजार करोड़ रुपए देने की पेशकश और उनका कबूलनामा भी मुद्दा नहीं बन पाए। बाकी कितना पैसा पकड़ा गया, कितनी शराब जब्त हुई, टाइप सूचनाओं से तो अब खर्च का हिसाब नहीं लगता। सभी दलों के मंडराते दर्जनों हैलीकाप्टर या चार्टर्ड विमानों का चुनावों पर कितना खर्च आया होगा, यह सोचा जा सकता है। हां इस बार बंगाल में बाहर से बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में गए वोटर ढोकर लाए गए, उसकी चर्चा जरूर हुई। पर हिंसा के मामले में तृणमूल कमजोर पड़ी हो, यह कहना मुश्किल है। भाजपा ने अपने भर प्रयास किया। और चाहे केन्द्रीय बलों की ताकत से हो या जैसे भी, लेकिन चुनाव अगर हिंसा से मुक्त हों, या इस बार पहले की तुलना में कम हिंसा हुई हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। टिकट बाहुबलियों को दिए गए। यह क्या है और इसके पीछे की मंशा क्या है, यह समझना आसान नहीं है। पर बंगाल चुनाव में हिंसा की परंपरा बनाने में वाम दलों की भी भूमिका रही है। और अगर कभी बिहार के चुनाव हिंसा के लिए बदनाम थे तो आज वह बदल चुका है। लेकिन बंगाल में चुनाव देश भर में सबसे ज्यादा हिंसक क्यों हैं, इस पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी को भी सोचना होगा।

इस बार बंगाल चुनाव मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और आखिरी दिन तक अदालती आदेश से वोट का हक पाने की उम्मीद लगाए लाखों वोटर मायूस हुए। योगेंद्र यादव का कहना है कि अक्तूबर 2025 को, अर्थात इस अभियान के शुरू होने से पहले राज्य की वयस्क आबादी 7.67 करोड़ थी और राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़। साफ है कि यहां ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले 58 लाख नाम काटे और फिर 60 लाख नामों पर 'लाजिकल डिस्क्रिपैंसी' का लाल झंडा गाड़ दिया गया। इनमें से ज्यादातर वोट के अधिकार से वंचित हुए। किस–किस तरह की गलतियां सामने आईं, यह गिनवाना बहुत होगा लेकिन जब लोग कलैक्टर को घेरने तक पहुंच गए, तब भी मामले को एकतरफा रखा गया। अदालती दखल भी चुनाव आयोग की तरफ झुका था। और जब इसी क्रम में ई.डी. के इस्तेमाल और सीधे मुख्यमंत्री द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया तो फिर इस सारे शुद्धिकरण अभियान की गंदगी जिसे न दिखी हो, वही अंधा कहलाएगा। हर राज्य में नामों में कतर–ब्योंत हुई, लेकिन बंगाल की तरह कहीं नहीं हुई। और यही कारण रहा कि ममता शासन के 15 साल का रिकार्ड और उससे पैदा नाराजगी के मुख्य चुनावी मुद्दा बनने की जगह मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही मुख्य मुद्दा बन गया। पता नहीं इससे ममता को लाभ होगा या भाजपा की मंशा इस बार पूरी हो जाएगी, यह 4 मई को साफ होगा।बंगाल जीतने की तमन्ना भाजपा के नेताओं के अंदर इस कदर हावी रही है कि उन्होंने सब कुछ किया और ममता बनर्जी ने भी जवाब देने में कमी नहीं की। इससे पहले चुनाव में मातुआ के नाम पर बंगाल के शांत समाज में जाति की फूट पैदा करने की कोशिश हुई तो उससे पहले हिन्दू–मुसलमान ध रुवीकरण का प्रयास हुआ। इन दोनों से नुकसान हुआ और अभी तक उसका असर है। लेकिन इस बार संसाधनों की बर्बादी और हिंसा के साथ एस.आई. आर. के नाम पर जो हुआ, वह लोकतंत्र पर तो कहीं भारी नहीं है। नाम काटना सिर्फ किरानीगीरी वाली भूल नहीं है। और जो यह कर–करा रहे हैं, उनको यह सब मालूम है। फिर भी यह हो रहा था, यही सबसे दुखद है। काश चुनाव के बाद चीजें सुधरें।

केजरीवाल की विचारहीन राजनीति का यही अंजाम होना था

अनिल जैन

निहित स्वार्थों से प्रेरित कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया के भरपूर समर्थन से परवान चढ़े एक विचारहीन और अराजक आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी का यही हश्र होना था, जो अभी हो रहा है। यह सही है कि आम आदमी पार्टी के विभाजन यानी राज्यसभा में उसके 10 में से 7 सांसदों को तोड़कर अपने पाले में लाने के काम को भाजपा ने अपने कु ख्यात ऑपेशन लोटस के जरिये अंजाम दिया है, जिसमें हमेशा की तरह उसने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का भी इस्तेमाल किया है। मगर आम आदमी पार्टी की इस स्थिति के लिए मूलतः उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने राज्यसभा के लिए अपने जैसे ही विचारहीन और सिद्धांतहीन लोगों का चयन किया था। इस सिलसिले में उन पर राज्यसभा के टिकट बेचने और अपने सजातीय लोगों को उपकृत करने के आरोप भी लगे। दरअसल डेढ़ दशक पहले 2011 में जब तथाकथित गांध ीवादी अण्णा हजारे को भ्रष्टाचार के विरोध का प्रतीक पुरुष बना कर दिल्ली के जंतर–मंतर पर आंदोलन किया जा रहा था, तब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उस आंदोलन की तुलना अरब स्प्रिंग और काहिरा (मिस्र) के तहरीर चौक पर हुई क्रांति से कर रहा था। कॉरपोरेट घरानों से पोषित टेलीविजन चौनलों पर उस आंदोलन का 24 घंटे सीधा प्रसारण हो रहा था। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के मंच से राजनीतिक दलों और नेताओं को चोर, बेईमान और भ्रष्ट करार देते हुए राजनीति से अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। उनके तेवरों को देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि जिस राजनीति को यह व्यक्ति पानी पी–पीकर कोस रहा है, कुछ ही महीनों बाद यही व्यक्ति उसी राजनीति का एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाएगा। टीवी चौनलों में कार्यरत कुछ पत्रकार तो केजरीवाल में श्दूसरा चे ग्वाराश और अण्णा हजारे में श्दूसरा गांधीश तक देखने लगे थे। मगर चंद महीनों बाद ही अण्णा हजारे से अलग होकर केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। आंदोलन की कोख से जन्मी उनकी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ शहरी मध्य वर्ग के गुस्से का प्रतिनिधित्व करती हुई एक विद्रोही पार्टी माना गया, जिसका गर्भधारण सड़कों पर विरोध–प्रदर्शनों से हुआ था। राजनीति को हिकारत से देखने वाले केजरीवाल इस पार्टी के माध्यम से राजनीति में आए और छा भी गए। तब केजरीवाल, उनके साथियों, प्रशंसकों और मीडिया के भी एक बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी के उदय को एक श्नई राजनीतिश के रूप में पेश किया था। हालांकि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास से और राजनीति को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाली ताकतों से परिचित लोग तब भी इस श्नयेपनश की हकीकत से बाखूबी वाकिफ थे। अण्णा–केजरीवाल के आंदोलन को काफी कुछ बौद्धिक ऊर्जा उस विवेकानंद फाउंडेशन से मिली थी, जो व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का थिंक टैंक है। उस आंदोलन के लिए सभी जरूरी साधन–संसाधन जुटाने में भी संघ का परोक्ष सहयोग था। आंदोलन के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ केजरीवाल और उनके साथियों की बैठकें भी होती थीं। हालांकि आम लोगों के सामने भी इस श्नयेपन की राजनीतिश को उजागर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जब 2014 आते–आते उस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरे भाजपा से जुड़ते गए और केंद्र में उसकी सरकार बनने पर ऊंचे–ऊंचे पदों को प्राप्त हो गए। अण्णा–केजरीवाल का भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन और आम आदमी पार्टी के उदय की परिघटना इस लिहाज से भी गौरतलब थी कि अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों की मदद से फल–फूल रहे गैर सरकारी संगठनों व एनजीओ ने जन–आंदोलनों की धार कुंद करते हुए आक्रामक तेवर के साथ राजसत्ता तक अपनी पकड़ मजबूत करने की मुहिम तेज कर दी थी। देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानों की हमदर्द इन एजेंसियों के सिपहसालार आम जनता की बदहाली और बेसब्री का फायदा उठाते हुए उसे यह समझाने में जुट गए कि भ्रष्टाचार, गरीबी और महंगाई जैसी दुश्वारियों से निजात पाने के लिए किसी विचार की जरूरत नहीं है। ऐसा समझाने वालों में खुद अरविंद केजरीवाल भी थे। फिर भी यह सच है कि इतना सब कुछ उजागर होने के बावजूद केजरीवाल दस साल मुख्यमंत्री भी रह लिए। इस दौरान एक विरोधाभासी नारा भी लगा– श्मोदी फॉर पीएम–केजरीवाल फॉर सीएमश इस नारे के अनुरूप केंद्र में मोदी की सरकार बनी और दिल्ली में केजरीवाल की। यह हैरानी की बात है कि एक ही मतदाता ने एक ही समय में दो अलग–अलग तरह की धाराओं में तैरने वालों को एक साथ कैसे चुन लिया? जाहिर है कि दोनों किरदारों के बीच दिखने वाला फर्क आभासी ही था। राजनीति को संभावनाओं का खेल माना जाता है तो केजरीवाल संभावनाओं की पैदाइश है । उनके पास अपनी राजनीति का कोई मौलिक विचार नहीं है। उन्होंने अपने को भाजपा से भी बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने के लिए कई हास्यास्पद उपक्रम किए। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए करेंसी नोटों पर लक्ष्मी–गणेश की तस्वीरें छापने जैसी मूर्खतापूर्ण मांग भी उन्होंने की। अपने को हनुमान भक्त बताया और लोगों को सरकारी खर्च पर अयोध्या सहित तमाम तीर्थस्थलों की यात्राएं भी कराईं। कोरोना महामारी के दौरान भाजपा की तर्ज पर तब्लीगी जमात के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने में भी उनकी सरकार ने कोई कोताही नहीं की और दिल्ली में दंगों के दौरान भी उनकी सरकार व पार्टी पीड़ितों के साथ न खड़ी होकर पुलिस के साथ और प्रकारांतर से केंद्र सरकार व भाजपा के साथ खड़ी दिखी। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर भी केजरीवाल भाजपा के साथ रहे। फिर जब उन्हें सुविध ाजनक लगा तो वह कांग्रेस के साथ चले गए। दिल्ली में पहली बार सरकार बनाने के लिए उस कांग्रेस से भी समर्थन लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ, जिसकी 15 साल पुरानी सरकार को उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हराया था। यह सब करना उनके लिए इसलिए आसान था क्योंकि उन पर विचारधारा का कोई बोझ नहीं था। यही वजह रही कि कई मौकों पर उन्होंने महात्मा गांध ी की समाधि पर जाकर अपने को बापू के प्रति आस्थावान दिखाया तो मौका आने पर अपनी पार्टी और सरकार के दफ्तरों से गांधीजी की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह भगत सिंह और डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल करने लगे। इस समय भी वे अदालती लड़ाई लड़ते हुए अपने को गांधी मार्ग का अनुगामी बता रहे हैं।

केजरीवाल की राजनीति सिर्फ विचारधारा विहीन ही नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी संगठनात्मक शक्ल देने में कोई रूचि नहीं दिखाई। अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और केजरीवाल इसके संयोजक बने थे। तब से लेकर आज तक वे ही इसके संयोजक बने हुए हैं। दिखावे के तौर पर पार्टी में एक राष्ट्रीय सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 34 सदस्यीय एक राष्ट्रीय परिषद भी हैं लेकिन व्यावहारिक तौर पर इन सबका कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल पार्टी के सुप्रीमो हैं और सारे फैसले वे ही करते हैं।

सीमा वर्णिका की कलम से

'अधूरा दहेज'

राखी वापस मायके आ गई पूरे मोहल्ले में खुसर पुसर हो रही थी।

अरे! बताओ.. दीवान साहब ने कितनी अच्छी शादी की थी.. लोग भी भले लग रहे थे.. पता नहीं क्या हुआ, रामेश्वर गुप्ता अपने मित्र शर्मा जी से मुख़ातिब होते हुए बोले।

आजकल का रवैया कुछ समझ नहीं आता ..शादी भी लॉटरी जैसी हो गई है.., खींसे निपोरते हुए शर्मा जी बोले ।

कितना दान दहेज दिया था दीवान साहब ने.. शादी का इंतजाम और लेन–देन..कई दिन तक चर्चा का विषय रहा था, गुप्ता जी चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले।

अरे ! जब संपन्न लोगों के यह हाल हैं तो हम मध्यमवर्गीयों का तो भगवान ही मालिक.., शर्मा जी ने अपनी बात जोड़ी।

हुआ क्या होगा.. यह तो पता चलता.. पर पूछे कौन, यादव जी ने कहा।

तभी अचानक किसी कार्य से दीवान साहब घर के बाहर आए।

अरे, आप लोग सब इकट्ठे यहाँ.. क्या हुआ.. कुछ खास बात., दीवान साहब ने पूछा।

नहीं.. नहीं.. कुछ खास नहीं.. बस गुप्ता जी सामने दिख गए तो दुआ सलाम हो गई, शर्मा जी झेंपते हुए बोले।

दीवान साहब ..बिटिया आयी है.. सब कुशल मंगल.. वह कामवाली कह रही थी.. हमेशा के लिए आ गई, यादव जी धीरे से बोले।

हाँ ..सही कह रही है वह... बिटिया अब यहीं रहेगी.., दीवान साहब ने मध्यम स्वर में जवाब दिया ।

भाई साहब आपने तो बहुत अच्छी शादी की थी.. खूब दिया लिया था ..ससुराल वालों को क्या कमी रह गई, गुप्ता जी बोले।

भाई ..सही कह रहे हो.. जो दे सकता था वह सब कुछ दिया ..पर अच्छी किस्मत देना किसी माँ–बाप के हाथ में नहीं होता.. , दीवान साहब छलछलाई आँखों को पोछते हुए वहाँ से चले गए।

सीमा वर्णिका,
कानपुर

चुनावी हिंसा रोकने में नाकाम आयोग

प. बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के मतदान से पहले भाजपा और चुनाव आयोग पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग ने उत्तरप्रदेश के आईपीएस अधिकारी और काउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के फौरन बाद अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वे फाल्टा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर के घर के पास खड़े हुए हैं और कहते हैं श्जहांगीर के घर वाले खड़े हैं, उसको बता देना कि कायदे से रहे... यह बार–बार जो खबर आ रही है कि जहांगीर के लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना और पछताना मत...। अजय पाल शर्मा की इस भाषा और धमकी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनाव निरीक्षक का काम चुनाव आयोग की आंख और कान की तरह काम करना है, लेकिन उसमें मुंह बंद रखना होता है। यानी ऐसे सरेआम किसी का नाम लेकर धमकाना सही नहीं है। अजय पाल शर्मा की नियुक्ति पर एक तरफ टीएमसी ने सवाल उठाए, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें संभल और रामपुर में भाजपा का परखा हुआ एजेंट कहकर बता दिया है कि इस नियुक्ति के पीछे राजनैतिक दबाव काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग को इस पर फौरन सफाई देनी चाहिए। क्योंकि लगातार प.बंगाल में आयोग की कामकाज की शैली पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग ने सोमवार, 27 अप्रैल को ही श्उपद्रवियोंश की एक नई सूची जारी की थी, जिसमें दूसरे दौर की 142 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हजारों लोगों के नाम शामिल हैं। इन सभी सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी इस सूची को एहतियाती कार्रवाई या हिरासत में लेने के अनुरोध के साथ जारी किया गया है। इसी तरह इस बार के चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए चुनाव आयोग ने केन्द्रीय बलों की 2400 कंपनियां यानी करीब 2.4 लाख जवानों को तैनात किया है, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए सभी 543 सीटों पर 3400 कंपनियां तैनात की गईं थी। इसके बावजूद राज्य में हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सोमवार को टीएमसी की महिला और अनुसूचित जाति से आने वाली सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। पत्थर बरसा कर उनकी कांच के शीशे तोड़े गए, जिसमें वो और उनका ड्राइवर दोनों घायल हुए हैं। टीएमसी का आरोप है कि हमला भाजपा के लोगों ने करवाया। एक पोस्ट में टीएमसी ने लिखा भी कि अमित शाह ने कहा था कि टीएमसी के लोगों को उल्टा लटका देंगे और अब ये हमला हुआ है। टीएमसी का ये भी आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर तैनात जवान और पुलिस निरीक्षक आधी रात को छापे मार रहे हैं, रात के सन्नाटे में आम नागरिकों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में जबरदस्ती घुस रहे हैंय वे परिवारों को आतंकित कर रहे हैं, मतदाताओं को डरा–धमका रहे हैं। वहीं मिताली बाग पर हुए हमले के बाद सागरिका घोष ने सवाल उठाया है कि क्या यही भाजपा की नारी शक्ति के सम्मान की हकीकत है। हालांकि ऐसा ही हमला गोगहाट में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत दिगार की गाड़ी पर भी किए जाने का आरोप लगा है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। इससे तीन दिन पहले एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई। इन हालात में सवाल ये है कि चुनाव आयोग के दावों का क्या हुआ। याद रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया था कि इस बार चुनाव में न छप्पा यानी फर्जी वोटिंग होगी और न ही बूथ जैमिंग यानी बूथ पर कब्जा होने दिया जाएगा। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की असली पहचान है और 2021 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। इस बार चुनाव आयोग की रणनीति पूरी तरह बदली हुई है। अब फोकस घटना होने के बाद कार्रवाई करने पर नहीं, बल्कि पहले से रोकथाम करने पर है। इसके लिए सुरक्षा बलों की पहले से तैनाती, संवेदनशील इलाकों की पहचान और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आयोग का साफ संदेश है कि चुनावी प्रक्रिया में डर, हिंसा और दबाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। याद रहे कि चुनाव की घोषणा होते ही प.बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे। लेकिन इतनी कवायद का क्या मतलब अगर सांसद या प्रत्याशी या किसी कार्यकर्ता पर हमले की घटनाएं रुके ही नहीं। पहले दौर के मतदान के दिन किस तरह सुवेंदु सरकार को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा गया था, वो नजारा भी जनता ने देखा है।

कौन है 2026 की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री ? प्रियंका चोपड़ा और दीपिका के अलावा ये एक्ट्रेस भी हैं शामिल

2026 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय अभिनेत्रियों की लिस्ट काफी लंबी है। इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण से लेकर प्रियंका चोपड़ा के अलावा कई अभिनेत्रियों का नाम शुमार है। ये हैं 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय अभिनेत्रियां, जिनकी फीस सुनकर आपको होश जरूर उड़ जाएंगे।प्रियंका चोपड़ा इस समय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में उन्होंने 30 करोड़ रुपये लिए हैं। उनकी एक फिल्म की फीस अब 40 करोड़ रुपये तक हो गई है। प्रियंका अब फिल्म 'वाराणसी' और सीरीज 'सिटाडेल 2' में नजर आएंगी।

दीपिका पादुकोण दूसरी बार मां बनने के बाद भी टॉप पर हैं। कथित तौर पर दीपिका एक फिल्म के लिए करीब 30 करोड़ रुपये फीस लेती हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में अल्लू अर्जुन के साथ 'राका' और शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' शामिल हैं। एटली कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म राका के लिए दीपिका को लगभग 25 करोड़ रुपये की फीस मिल रही है।

आलिया भट्ट भी बहुत ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। आलिया अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये फीस लेती हैं। आलिया फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म लव एंड वॉर के लिए आलिया करीब 7 करोड़ रुपये फीस ले रही हैं। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आलिया फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सकती हैं।

स्त्री 2 की जबरदस्त सफलता के बाद श्रद्धा कपूर ने अपनी फीस बढ़ा दी है। श्रद्धा अपनी आगामी फिल्मों के लिए अच्छी फीस की डिमांड कर रही हैं। उनकी एक फिल्म की फीस 25 से 30 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। वे 'नागिन' और 'स्त्री 3' जैसी फिल्मों में काम कर रही हैं।

कटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं। कटरीना अभी बच्चे के साथ समय बिता रही हैं। कटरीना की एक फिल्म की फीस 15 से 21 करोड़ रुपये के बीच है। टाइगर 3श्जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए कटरीना ने 15 से 21 करोड़ के बीच फीस ली थी। फिल्मों के अलावा, कटरीना ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी कमाई करती हैं। करीना बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री करीना कपूर खान एक प्रोजेक्ट के लिए कथित तौर पर करीब 18 करोड़ रुपये फीस लेती हैं। करीना जल्द ही फिल्म 'दायरा' में नजर आएंगी। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस क्राइम थ्रिलर फिल्म श्दायराश में करीना के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2025 में पूरी हो चुकी है। यह फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है।

`पंजाब की ऐश्वर्या राय' का ग्लैमरस अवतार, देसी अंदाज में मिला मॉडर्न ट्विस्ट

पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। 'पंजाब की ऐश्वर्या राय' के नाम से मशहूर हिमांशी ने इस बार ऐसा लहंगा लुक कैरी किया कि सोशल मीडिया पर हर कोई बस उन्हें ही देखता रह गया। देसी एलीगेंस के साथ मॉडर्न टच का उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बार हिमांशी डीप नेवी ब्लू कलर के मरमेड स्टाइल लहंगे में नजर आईं, जिसकी कीमत करीब 50,600 बताई जा रही है। पूरे लहंगे पर लगे चमचमाते सेक्विन्स उनके लुक को बेहद ग्लैमरस बना रहे थे। यह आउटफिट ऐसा था, जो वेडिंग फंक्शन से लेकर रेड कार्पेट तक हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट नजर आता है।

लहंगे की स्कर्ट को नेट फैब्रिक से तैयार किया गया था, जिस पर सेक्विन, थ्रेड वर्क और कटवर्क की बारीक डिटेलिंग की गई। इसका मरमेड सिल्हूट खास रहा ऊपर से बॉडी–हगिंग और घुटनों के नीचे से फ्लेयर्ड, जिसने उनके कर्व्स को बेहद खूबसूरती से हाइलाइट किया। यही डिजाइन इस लुक को ड्रामेटिक और स्टाइलिश बना गया। इस लुक की असली हाइलाइट उनकी चोली रही। स्ट्रैपलेस डिजाइन के साथ कर्व कट नेकलाइन और हॉल्टर नेक पैटर्न ने इसे और भी ग्लैमरस बना दिया। बैक साइड पर डीप नेक और कटआउट स्ट्रैप्स ने इसमें बोल्ड टच जोड़ा। चोली पर बने स्क्वायर सेक्विन पैटर्न ने पूरे लुक को शिमरी और यूनिफॉर्म फिनिश दिया। जहां पूरा आउटफिट काफी हैवी और शिमरी था, वहीं हिमांशी ने दुपट्टे को सिंपल और लाइट रखा। सिर्फ बॉर्डर पर हल्की सेक्विन डिटेलिंग के साथ प्लेन दुपट्टा लुक को ओवरडन होने से बचा गया। इससे उनका पूरा स्टाइल बैलेंस्ड और एलिगेंट नजर आया। हिमांशी ने अपने इस लुक को स्टेटमेंट जूलरी के साथ पूरा किया। उन्होंने व्हाइट फिनिश ब्लू हार्ट–शेप डायमंड चोकर सेट पहना, जिसके साथ मैचिंग इयररिंग्स बेहद खूबसूरत लगे। सॉफ्ट वेवी हेयर और नैचुरल ग्लैम मेकअप ने उनके पूरे लुक को और निखार दिया। अगर आप वेडिंग सीजन के लिए कुछ अलग और स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो हिमांशी का यह लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है रॉयल ब्लू या डीप शेड्स के सेक्विन लहंगे चुनें, मरमेड स्टाइल अपनाएं जिससे लुक डिफरेंट लगे जूलरी में एक स्टेटमेंट पीस रखें, हैवी आउटफिट के साथ दुपट्टा लाइट रखें।

संजय दत्त को भाया 'आखरी सवाल' का दमदार प्लॉट, तुरंत कर दी हां

संजय दत्त स्टारर आखरी सवाल सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है और दर्शक इसकी रिलीज का बेसब्री से राह देख रहे हैं। इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी चर्चा थी और फिर मेकर्स ने हनुमान जयंती पर फिल्म का टीजर रिलीज किया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के इतिहास की ऐसी झलक दिखाई गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जहाँ हर कोई फिल्म का इंतजार कर रहा है, वहीं डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग ने आखरी सवाल की स्क्रिप्ट सुनने के बाद संजय दत्त के रिएक्शन के बारे में बताया है। आखरी सवाल की स्क्रिप्ट पर संजय दत्त के रिएक्शन को साझा करते हुए डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग ने कहा, "जब संजय ने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी, तो वो तुरंत इससे जुड़ गए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का वो अनकहा अध्याय है जिसे बताया जाना बहुत जरूरी है।

इश्क ऐसा कि सुतापा के प्यार में धर्म बदलने को तैयार हो गए थे इरफान खान

इरफान खान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उन्हें दुनियां से गए 6 साल हो गए हैं लेकिन वो अभी भी अपने फैंस के दिलों में राज करते हैं। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान ने दुनियां को अलविदा कहा था। आज उनकी पुण्यतिथि पर इरफान की पत्नी सुतापा ने बहुत ही इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जिसकी वजह से इन दोनों की लव स्टोरी फिर से सुर्खियों में आ गई है। बता दें कि जब उनकी पत्नी इरफान खान को याद करती हैं, तभी वो अपने सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ जरूर पोस्ट करती हैं। दोनों का प्यार इतना अटूट है कि चाह कर भी इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो चलिए आज जानते हैं इरफान खान और सुतापा के इश्क की दास्तां कि कैसी शुरू हुई इनकी लव स्टोरी। इरफान खान की लव स्टोरी किसी मूवीज से कम नहीं है। उनके प्यार की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। बता दें कि 23 फरवरी 1995 में इरफान खान की शादी सुतापा से हुई थी। दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से दोनों की इश्क की स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले तो दोनों दोस्त बने और फिर उसके बाद से ही दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। हालांकि पहली नजर में ही इरफान सुतापा को अपना दिल दे बैठे थे लेकिन प्यार में पड़ने से पहले दोनों ने दोस्ती का सहारा लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक्टिंग करते हुए एक–दूसरे से मिले थे। ज्यादातार दोनों काम और फिल्मों को लेकर ही बातचीत करते थे और दोनों का नजरिया एक जैसा ही था। इसके बाद ही दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने लगी। प्यार में पड़ने के बाद दोनों ने फैसला लिया की एक–दूसरे को समझने के लिए दोनों एक–साथ रहेंगे। इस दौरान दोनों अपने करियर पर फोकस देते थे लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ की सब कुछ बदल गया। हुआ कुछ यूं कि सुतापा प्रेग्नेंट हो गईं और ज्यादा सवाल–जवाब से बचने के लिए दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया और साल 1995 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों के बीच प्यार कुछ इस कदर था की सुतापा के साथ शादी करने के लिए इरफान खान अपना धर्म बदलने को भी तैयार हो गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान इरफान खान ने यह बात बोली थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद दोनों के दो बेटे हुए। परिवार तो पूरा हो गया लेकिन किस्मत ने इरफान खान का साथ नहीं दिया और 29 अप्रैल 2020 में कैंसर के चलते इरफान दुनियां को अलविदा कह गए।

अर्जुन कपूर का इमोशनल पोस्ट, बहन अंशुला के लिए जताया प्यार

क्या हम सब कभी न कभी यह नहीं सोचते कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कहीं शांति वाली जगह पर चले जाएं? अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर अभी यही कर रहे हैं और साथ में होने से यह पल और भी खास बन गया। अर्जुन ऑस्ट्रिया के विवामायर मारिया वर्थ गए थे, जहां उन्होंने अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लिया। यह जगह शांति और हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है, इसलिए उनके लिए यह एक परफेक्ट ब्रेक साबित हुआ। अर्जुन ने लिखा, जेन जैसा सुकून। पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद को थोड़ा ध ीमा किया। न कोई जल्दी, न ज्यादा काम३ बस हर पल को जीया। अब मैं खुद को हल्का और फ्रेश महसूस कर रहा हूं। उनका यह छोटा सा मैसेज बहुत कुछ कह गया। हमेशा व्यस्त रहने वाली जिंदगी में उन्होंने आराम और सुकून को अहमियत दी, जो लोगों को अच्छा लगा। इस पोस्ट की सबसे खास बात थी उनकी बहन के लिए प्यार। उन्होंने लिखा, अंशुला के बिना यह हफ्ता इतना आसान नहीं होता। अर्जुन और अंशुला हमेशा एक–दूसरे के साथ रहे हैं अच्छे और बुरे हर समय में। यह ट्रिप दिखाता है कि हमें अपने अपनों के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। यह सिर्फ छुट्टी नहीं थी, बल्कि सुकून, साथ और रिश्तों की अहमियत समझने का समय था।

स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं आपके बच्चे, इन लक्षणों के दिखने पर बरतें पैरेंट्स सावधानी

यादा इस्तेमाल करने से आजकल स्लीप डिसऑर्डर की समस्या बहुत आम हो गई है। पूरा दिन की थकान के बाद भी कई बार अच्छे से नींद नहीं आ पाती इसी समस्या को स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में हुए शोध की मानें तो करीबन 25प्रतिशत बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। पूरी नींद न लेने के कारण बच्चे को कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो

सकती हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं...

इतनी तरह के स्लीप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं बच्चे

एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चे नींद में गड़बड़ी, नींद में डर लगना या बुरे सपने आना स्लीप डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। इसके कारण बच्चे को अनिद्रा, हाइपरसोमनिया, पैरासोमनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और नार्कोलेप्सी जैसी समस्याएं भी खड़ी होने लगती हैं। इसके अलावा बच्चों को ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे नींद के दौरान आराम से सांस भी नहीं ले पाता।

ये हैं स्लीप डिसऑर्डर के लक्षण?

. यदि बच्चे रात में देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं।

. बच्चे रात में बार–बार नींद से जागते हैं या दोबारा से सोने में परेशान होते हैं।

. यदि बच्चे दिन में 10–15 मिनट की कई झपकियां लेते हैं।

. खेलने–कूदने की जगह यदि बच्चे शांत बैठे रहते हैं।

. यदि उनकी डेली रुटीन की खाने–पीने की आदतों में बदलाव आया है।

. बच्चा हर समय यदि सुस्त रहता है

. छोटी–छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन होना

कारण

स्लीप डिसऑर्डर के बच्चों में कई कारण हो सकते हैं जैसे खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ट्रॉमा, प्रदूषण, एलर्जी, पढ़ाई का स्ट्रेस और गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना । इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण जैसे एडीएचडी और ऑटिज्म भी इसका कारण हो सकते हैं।

क्या पड़ता है बच्चे पर इसका प्रभाव?

पूरी नींद न आने के कारण बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके कारण बच्चे की एनर्जी और सारी दिन की एक्टिविटीज पर प्रभाव पड़ता है।

. इसके अलावा बच्चे में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मूड स्विंग्स जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं।

. इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है जिसके कारण बच्चे बहुत ही जल्दी इंफेक्शन की चपेट में आ सकते हैं।

. स्लीप डिसऑर्डर के कारण बच्चे की एकाग्रता और मेमोरी पावर प्रभावित होने लगती है।

. नींद की कमी और अनिद्रा के कारण ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण भी बन सकता है। इसके कारण कार्डियोवैस्कुलर रोग और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

. नींद न आने के कारण बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद जरुरी है इसके अलावा बच्चों के अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पूरी मात्रा में नींद जरुरी है। यदि बच्चों में इनमें से एक लक्षण भी दिखे तो एक बार हैल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह जरुर ले लें।

गर्मियों में सुबह- सुबह चबा लें ये चमत्कारी पत्ता, डायबटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों की होगी छुट्टी

गर्मियों के मौसम में कई लोग शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चीजों का सहारा लेते हैं। ऐसा ही एक पौधा है। जिसे आम भाषा में शहतूत कहा जाता है। जहां इसके फल स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, वहीं इसके पत्ते भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य समस्याओं में किया जाता रहा है। आइए जानते हैं गर्मियों में शहतूत के पत्ते चबाने से शरीर को क्या–क्या फायदे मिल सकते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद

शहतूत के पत्तों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ शोधों के अनुसार यह टैप 2 डायबटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। गर्मियों में शरीर में गर्मी और थकान बढ़ जाती है। शहतूत के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ठंडक देने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

पाचन को बेहतर बनाते हैं

शहतूत के पत्तों में फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे कब्ज और पेट से जुड़ी छोटी समस्याओं से राहत मिल सकती है।इन पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद

कुछ अध्ययनों के अनुसार शहतूत के पत्ते खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर रखने में सहायक हो सकते हैं। इससे भ्मंतज क्पेमेंम का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है।

सेवन कैसे करें?

सुबह खाली पेट 2,3 ताजे शहतूत के पत्ते अच्छी तरह धोकर चबाएं। चाहें तो इनके पत्तों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक चीज का अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आप दवा ले रहे हैं, तो शहतूत के पत्तों का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। शहतूत के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और गर्मियों में इनका सीमित मात्रा में सेवन ब्लड शुगर कंट्रोल, पाचन सुधारने और शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है।

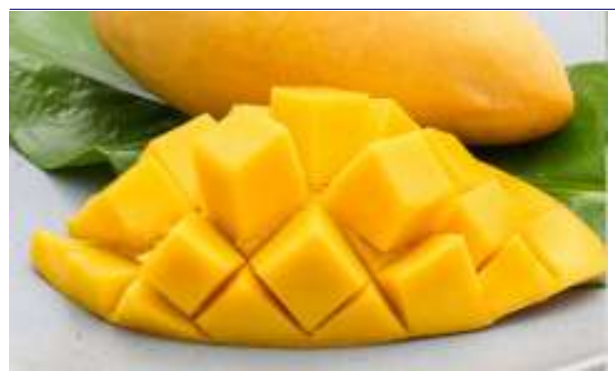

स्वाद में रसीला आम बच्चों को देगा कई फायदे, गर्मियों में रोज खिलाने से होंगे ढेरों हेल्थ बेनिफिट

गर्मियों में मीठा रसीला आम मिल जाए तो स्वाद ही अलग होता है। खासकर इस मौसम में बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे सभी इन्हें खाना पसंद करते हैं। स्वाद में भरपूर होने के साथ–साथ यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता हैं। यह पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। बच्चों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं गर्मियों में बच्चों को आम खिलाने से क्या–क्या फायदे होंगे...

आंखों की रोशनी और मस्तिष्क का करेगा विकास

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बच्चों के लिए आम बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसका उन्हें सेवन करवाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, पाचन स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क का विकास होने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा आम बच्चों को किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचाने में भी मदद करता है।

पोषक तत्वों से भरपूर होता है आम

आम में टरपीन, एस्टर और एल्डिहाइड जैसे एंजाइम्स और बायो कैमिकल्स पाए जाते हैं। यह कैमिकल्स पाचन सुधारने में मदद करते हैं। इसके अलावा पके आम में विटामिन–ए पाया जाता है जो शिशु की आंखों को रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा आम में विटामिन–सी, बी, आयरन, पौटेशियम और प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो बच्चो के स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है।

किन बच्चों को दे सकते हैं आम?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, आप शिशु को 8–10 महीने के बाद आम खिला सकते हैं। इसमें पाया जाने वाला फाइबर उनका पाचन सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा यदि आपके बच्चे शारीरिक रुप से कमजोर हैं तो उन्हें मैंगो शेक बनाकर पिला सकते हैं।

आम के बच्चों के लिए अन्य फायदे

दिमाग और हड्डियों का विकास

आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व दिमाग और हड्डियों का विकास करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और बेटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो हड्डियां मजबूत बनाता है। आम में विटामिन–बी और ई भी मौजूद होता है जो दिमाग तेज करने में मदद करता है।

देता है शरीर को एनर्जी

बच्चे खेलने–कूदने के चक्कर में अक्सर एनर्जी खो देते हैं ऐसे में आप उन्हें एनर्जी देने के लिए आम खिला सकते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन–बी6 और बी2 एनर्जी देने में मदद करता है। शाम के समय आप उन्हें आम खिला सकते हैं।

मजबूत बनेगी इम्यूनिटी

इसमें विटामिन–सी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है ऐसे में यह इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मदद करता है। यदि आप बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक आम जरुर खिलाएं। यह इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आम में विटामिन–ई और विटामिन–बी 6 भी मौजूद होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है।

गर्मी के असर को कम करेंगी ये 6 होममेड ड्रिंक्स

गर्मी आते ही सबका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में गर्मी में ताजगी महसूस करने के लिए ड्रिंक्स बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह ना सिर्फ आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि आपके शरीर को कई पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। कूलिंग ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन के बजाय घर पर बनें ड्रिंक्स का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आइए जानते हैं गर्मियों से राहत दिलाने के लिए किन ड्रिंक्स का सेवन करना लाभकारी होता है।

तरबूज का जूस

तरबूज के रस में 96 प्रतिशत पानी होता है साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, बी6, सी आदि एंटी–ऑक्सीडेंट्स होते हैं। यहीं कारण है कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज का स्वादिष्ट जूस पीना लाभकारी होता है।

नींबू पानी

नींबू पानी में विटामिन सी होता है। यह बीमारियों से बचाने के लिए शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है साथ ही यह शरीर को हाइड्रेट भी रखता है इसलिए गर्मियों में नींबू पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

नारियल पानी

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए साधारण पानी की जगह नारियल पानी एक बेहतर विकल्प होता है। यह विटामिन ई से भरपूर है। खुद को हाइड्रेट और स्वस्थ रखने के लिए आप रोजाना नारियल पानी पिएं।

छाछ

भारतीय घरों में गर्मी के दौरान छाछ पी जाती है। छाछ दूध से बनी होती है और इसमें कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, प्रोटीन जैसे स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। छाछ पीने से डिहाइड्रेशन और कब्ज की समस्या नहीं होती इसलिए गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छाछ पीना फायदेमंद होता है

आम का पन्ना

गर्मियों में लू से बचाने में आम का पन्ना काफी फायदेमंद साबित होता है। कच्चे आम को छिलकर उबाल लें। उसमें नमक, पुदीना, शक्कर डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। फिर गिलास में डालकर बर्फ मिक्स कर लें। इससे गर्मी में राहत मिलेगी।

पुदीने का शरबत

गर्मी में डिहाइड्रेशन और लू से बचने के लिए मिक्सी में पुदीना, चीनी, शहद, काला नमक, कालीमिर्च और जीरा पाउडर मिलाकर पीस लें।

संक्षिप्त

पावरग्रिड को एसबीआई से मिलेगा 4000 करोड़ रुपये का फंड, निदेशक मंडल ने दी अनसिक्योर्ड लोन को मंजूरी

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के ऊर्जा क्षेत्र से एक बड़ी कॉर्पोरेट खबर सामने आ रही है। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने धन जुटाने के लिए एक अहम वित्तीय फैसला लिया है। कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से 4,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली इस दिग्गज कंपनी ने गुरुवार को इस संबंध में एक अहम घोषणा की। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई अपनी आधिकारिक फाइलिंग में सूचित किया है कि निदेशक मंडल की बैठक में भारतीय स्टेट बैंक से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार की अनुकूल नीतियों के दम पर देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक नए ऐतिहासिक स्तर की ओर बढ़ रहा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का कुल एफडीआई 90 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी के बीच ही एफडीआई का प्रवाह 88 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो वैश्विक निवेशकों के भारतीय बाजार पर बढ़ते भरोसे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल के समय में लगातार कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। सचिव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश में लागू किए गए बड़े नीतिगत सुधारों, विभिन्न देशों के साथ हो रहे मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और भारत की तेज आर्थिक विकास दर ने मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित निवेश का माहौल तैयार किया है। इन तमाम सकारात्मक कारकों और पहलों की मदद से स्वस्थ निवेश आकर्षित करने में काफी मदद मिल रही है, जिससे पूरे वित्त वर्ष की समाप्ति तक 90 अरब डॉलर के बड़े मील के पत्थर को हासिल करने का लक्ष्य अब पूरी तरह से संभव नजर आ रहा है।

लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 583 अंक टूटा, 24000 के नीचे निफ्टी

नई दिल्ली,एजेंसी। वैश्विक दबाव और पश्चिम एशिया में गहराते भू–राजनीतिक तनाव का सीधा असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल के कारण घरेलू बाजार में भारी बिकवाली हुई, जिससे बीएसई सेंसेक्स 582.86 अंक गिरकर 76,913.50 पर बंद हुआ। निफ्टी 180.10 अंक गिरकर 23,997.55 पर आ गया। बाजार में शुरुआती कारोबार से ही भारी दबाव देखा गया। बाजार में इस भारी बिकवाली का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल है। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 121 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया था, जो पिछले चार वर्षों का उच्चतम स्तर है। हालांकि, बाद में यह 1.22 प्रतिशत गिरकर 116.59 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 108 डॉलर के करीब पहुंच गया। यह ऊर्जा संकट अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक ईरान के साथ नया परमाणु और सुरक्षा समझौता नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिका द्वारा जलडमरूमध्य खोलने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज करने से तेल आपूर्ति लंबे समय तक बाधित होने की आशंकाएं और गहरी हो गई हैं। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा के अनुसार, भारत एक प्रमुख तेल आयातक देश है, इसलिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रुपये में कमजोरी– अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर 95 रुपये के करीब पहुंच गया है और बॉन्ड यील्ड में भी तेजी दर्ज की जा रही है। बाजार पर दोहरा दबावरू विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की निकासी और गुरुवार को बीएसई अनुबंधों की मासिक एक्सपायरी ने बाजार की गिरावट और अस्थिरता को और तेज कर दिया। केवल भारतीय बाजार ही नहीं, बल्कि एशियाई बाजारों में भी निराशाजनक रुख देखा गया। जकार्ता कंपोजिट में 2.08 प्रतिशत, हैंग सेंग में 1.39 प्रतिशत और निक्केई 225 में 1.29 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अमेरिकी बाजारों में भी मिला–जुला लेकिन नकारात्मक रुख रहाय डाउ जोंस 0.18 प्रतिशत और एसएंडपी500 0.04 प्रतिशत लाल निशान में रहे, जबकि नैस्डैक में 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई।

रियान पराग पर बीसीसीआई ने लगाया भारी जुर्माना, खाते में एक डेमिरेट अंक भी जुड़ा, क्यों हुई कार्रवाई?

नई दिल्ली,एजेंसी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। रियान पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है, जबकि आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन पर उनके खाता में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। रियान ने राजस्थान और पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 40वें मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था जिसे लेकर अब कार्रवाई की गई है। पंजाब किंग्स के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले के दौरान वह ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते कैमरे में दिखाई दिए। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस समय राजस्थान 223 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। वीडियो में पराग के आसपास यशस्वी जायसवाल, युधवीर सिंह चरक और कुलदीप सेन भी नजर आए। यह दूसरी बार है जब राजस्थान रॉयल्स मैदान के बाहर के मामले में विवादों में घिरी है। इससे पहले रोमी भिंडर के डिवाइस इस्तेमाल का मामला सामने आया था।

आईपीएल ने बयान में कहा, रियान को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो खेल भावना के विरुद्ध आचरण से संबंधित है। यह घटना दूसरी पारी के दौरान घटी जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। रियान पर मैच रेफरी अमित शर्मा ने जुर्माना लगाया जिसे राजस्थान के कप्तान ने स्वीकार किया है। बीसीसीआई टीम, उनके अधिकारी और खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया के लिए अन्य विकल्प भी तलाश रहा है जिससे आईपीएल की प्रतिष्ठता बरकरार रहे। पता चला है कि मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म

होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की शिकायत नहीं की थी। उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने इसका वीडियो सबूत देखा। इसके बाद शर्मा ने आईपीएल के नियमों के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पराग को दोषी पाया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जैसा कि बयान में साफ–साफ लिखा है हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। भारत में ई–सिगरेट और वेपिंग द प्रोहिबिशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट, 2019 के तहत प्रतिबंधित है। इस कानून के तहत इनके निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर रोक है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। राजस्थान के लिए आईपीएल का मौजूदा सीजन अच्छा जा रहा है। टीम नौ मैचों में छह जीत और तीन हार के साथ 12 अंक लेकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है। राजस्थान का सामना अब एक मई को दिल्ली कैपिटल्स से होगा।

मौजूदा सीजन में शतक जीत की गारंटी नहीं, पांच बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम को नहीं मिली जीत

नई दिल्ली,एजेंसी। टी20 में शतक लगाना बड़ी उपलब्धि माना जाता है। किसी बल्लेबाज ने अगर टी20 मुकाबले में शतक लगा दिया, तो उसकी टीम की जीत सुनिश्चित मानी जाती है, लेकिन आईपीएल 2026 में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस सीजन में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की टीमें जीती हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है जिनके शतक उनकी टीम को जीत नहीं दिला सके। आईपीएल 2026 में 29 अप्रैल तक 41 मैच खेले गए। इन 41 मैचों में नौ शतकीय पारियां आई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दो, सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक, मुंबई इंडियंस के तीन बल्लेबाजों तिलक वर्मा, क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकेल्टन ने एक–एक, दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने एक, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने एक और राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने एक शतक लगाया है। कुल नौ शतकों में सिर्फ चार बार ही ऐसा हुआ है जब टीमें जीती हैं। पांच बार शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की टीम हारी है।

सीएसके के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने सीजन में दो शतक (दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस) के खिलाफ लगाए हैं। दोनों मैचों में सीएसके को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया था। मुंबई को इस मैच में जीत मिली थी। सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक लगाया था और इस मैच में उनकी टीम को जीत मिली थी। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने पंजाब किंग्स और रेयान रिकेल्टन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन दोनों ही मैचों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने अपने करियर की श्रेष्ठ पारी (152 रन)

खेली थी, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली गई यह पारी दिल्ली के काम नहीं आई और टीम को रिकॉर्ड हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ शतक लगाया, लेकिन उनकी टीम हारी। क्रिकेट की दुनिया में नई सनसनी बन चुके राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था।

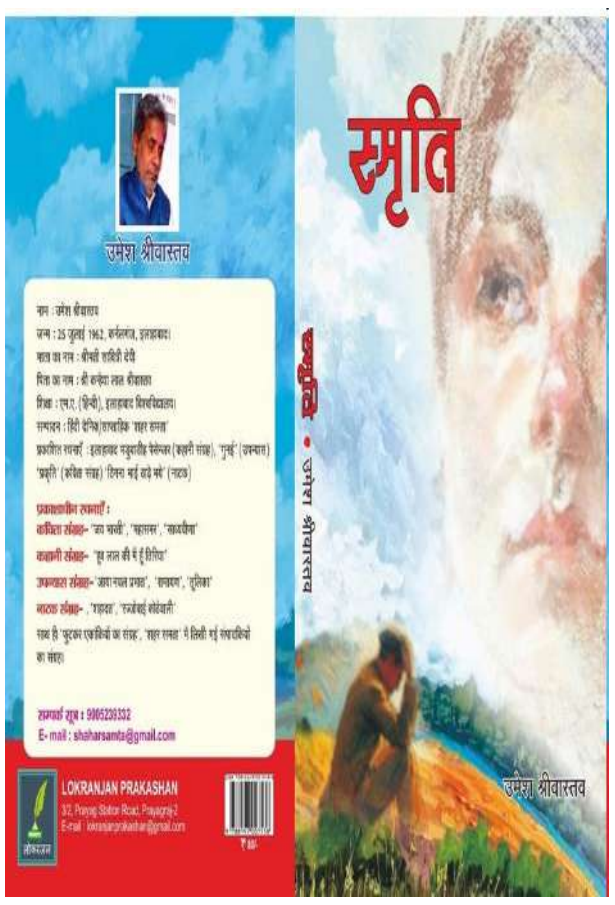

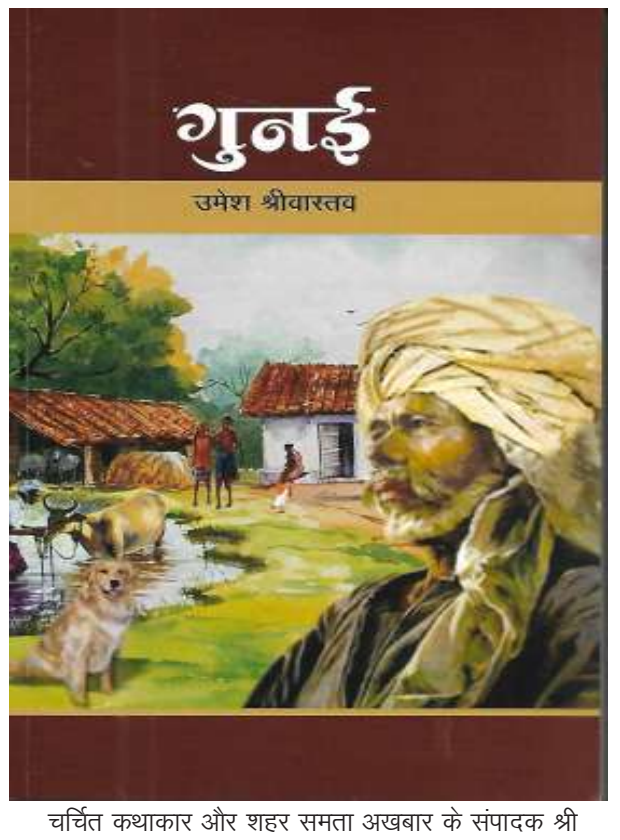

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

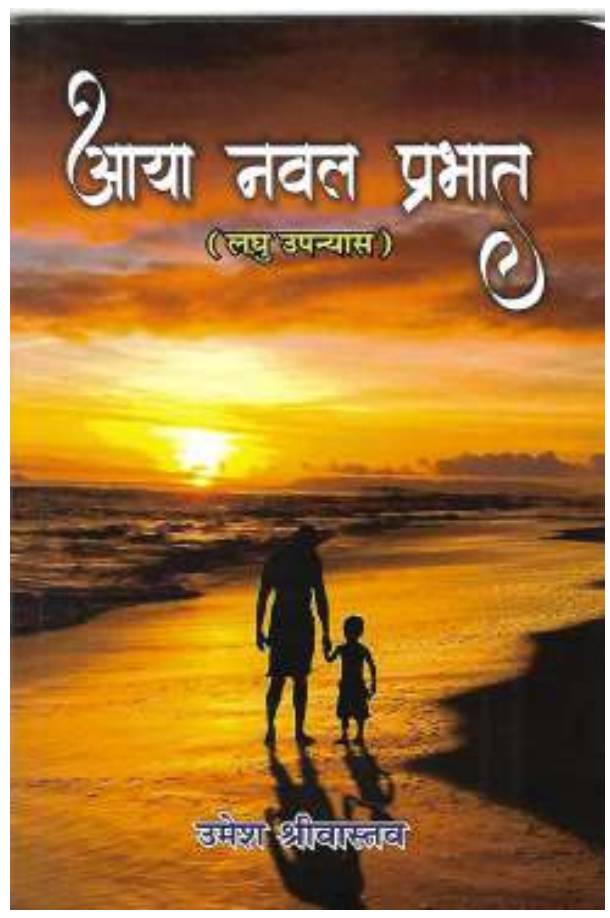

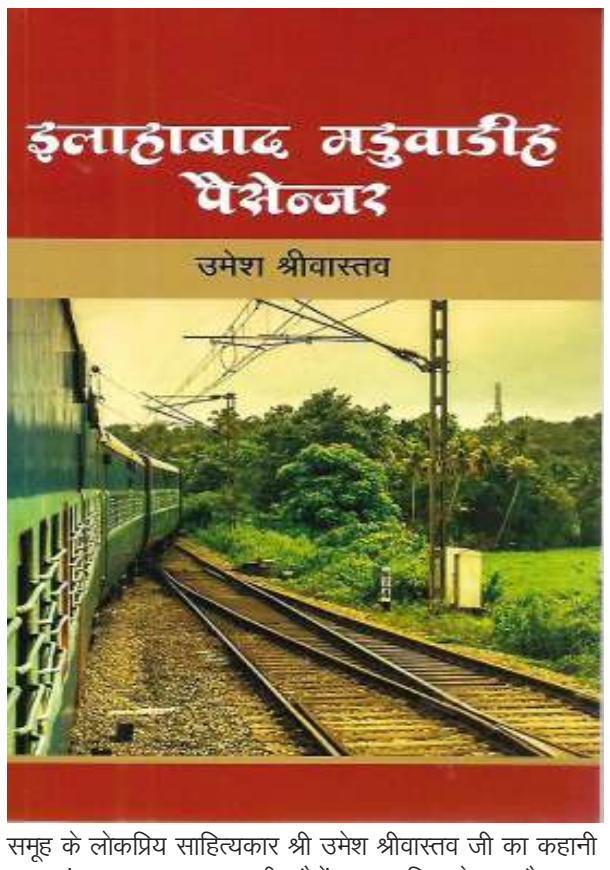

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

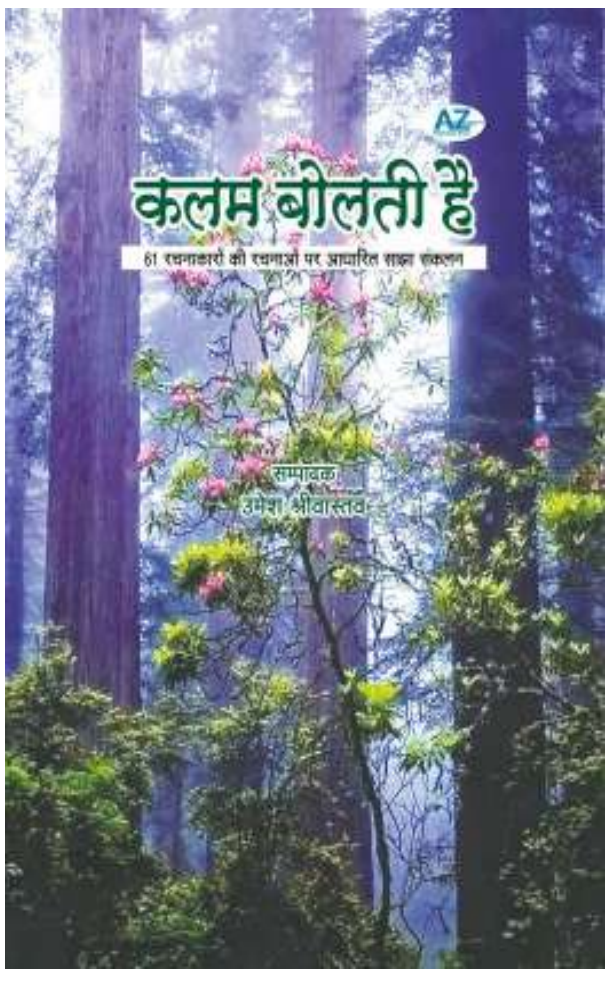

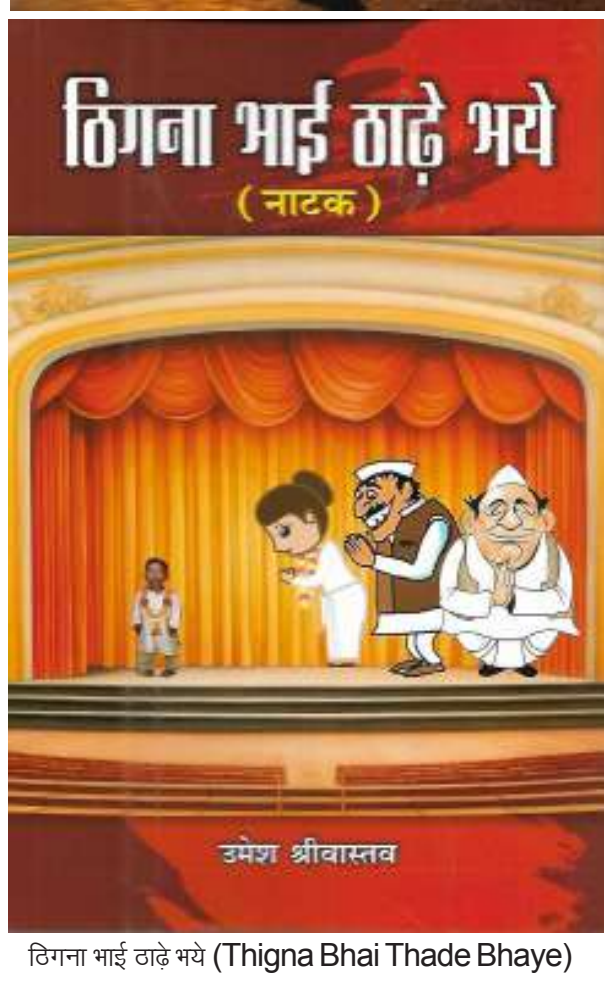

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त

अमेरिकी सेना की ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी, 42 जहाजों को रोका, ईरान ने ऐसे दिया जवाब

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि उसने ईरानी बंदरगाहों में समुद्री वाणिज्य को रोकने के लिए लगाई गई नाकेबंदी के तहत 42 जहाजों को रोका है। यह कार्रवाई ईरान के तेल निर्यात से होने वाले संभावित राजस्व

को बाधित करने के उद्देश्य से की गई है। ईरान ने इस कार्रवाई को खुले तौर पर समुद्री डकैती करार दिया है और अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर अमेरिका ने दी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे 42वें वाणिज्यिक जहाज को रोका है। उन्होंने बताया कि नाकेबंदी में अभी 41 टैंकर फंसे हुए हैं। इन टैंकरों में अनुमानित 690 लाख बैरल तेल है, जिसका संभावित राजस्व 6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ईरान ने इसे डकैती बताया कमान, खातम अल–अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने बताया कि सशस्त्र बलों ने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि चालक दल के सदस्यों के परिवार जहाज पर सवार थे। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया है। राज्य–संचालित प्रेस टीवी ने पहले एक उच्च पदस्थ सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया था कि इस पर जल्द ही व्यावहारिक और अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई की जाएगी। क्यों की गई है नाकेबंदी संयुक्त राज्य अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकेबंदी लगाई है। यह नाकेबंदी जहाजों को ईरानी बंदरगाहों से आने–जाने से रोक रही है। यह नाकेबंदी ईरान–अमेरिका वार्ता के विफल होने के बाद प्रभावी हुई। यह वार्ता 11–12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी।

होर्मुज सुरक्षा के लिए अमेरिका बनाएगा नया गठबंधन, वैश्विक व्यापार-ऊर्जा संकट से बढ़ी चिंता

वॉशिंगटन, एजेंसी। वॉशिंगटन में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक बड़ी रणनीतिक पहल शुरू की है। व्हाइट हाउस अब एक नए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन को तैयार करने की कोशिश में है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। क्या है नया मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट? अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रस्तावित योजना का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट (एमएफसी) रखा गया है। इसका मकसद विभिन्न देशों को एक साथ लाकर समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को मजबूत करना है। इस योजना में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड मिलकर काम करेंगे। विदेश विभाग कूटनीतिक नेतृत्व करेगा, जबकि सेंट्रल कमांड समुद्री निगरानी और सूचना साझा करने का जिम्मा संभालेगा। वैश्विक देशों से समर्थन की अपील अमेरिका अपने साझेदार देशों से इस गठबंधन में शामिल होने की अपील कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह भी पूछा जा रहा है कि क्या देश इस पहल में राजनयिक या सैन्य साझेदार बनना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सामूहिक कार्रवाई से वैश्विक व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया जा सकेगा और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम होगा। ईरान के साथ तनाव और समुद्री टकराव यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि जब तक ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता, तब तक समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी। वहीं ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि इस नाकाबंदी का जवाब अभूतपूर्व कार्रवाई से दिया जाएगा। आगे क्या हो सकता है? अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि यह संघर्ष आगे बढ़कर या तो किसी नए परमाणु समझौते में बदल सकता है या फिर लंबा सैन्य तनाव बन सकता है। फिलहाल, दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह नया गठबंधन समुद्री व्यापार को स्थिर कर पाएगा या नहीं।

ट्रंप को धमकी देने के आरोप में फंसे एफबीआई के पूर्व प्रमुख, ट्रंप बोले- जेम्स कोमी बुरे और भ्रष्ट आदमी हैं

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के पूर्व प्रमुख जेम्स कोमी पर बुधवार को तीखा हमला बोला और जेम्स कोमी को बुरा और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी बताया। जेम्स कोमी, डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कथित धमकी देने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जेम्स कोमी ने एक रहस्यमयी पोस्ट किया था, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने जेम्स कोमी को लेकर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, श्अगर कोई भी अपराध के बारे में जानता है तो उन्हें पता होगा कि 86 का मतलब क्या होता है।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र

शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र

मोबाईल नम्बर. 9190052 39332

.919450482227

किंग चार्ल्स का अमेरिका दौरा क्यों है खास ? शाही परिवार की सॉफ्ट पावर से बन सकती है बिगड़ी बात

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका इस सप्ताह ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला के राजकीय दौरे की मेजबानी कर रहा है। किंग चार्ल्स का यह दौरा कई मायनों में खास है। दरअसल यह दौरा एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में आ रही खटास को खत्म करने का अहम मौका है और इसमें ब्रिटेन की शाही परिवार की सॉफ्ट पावर बेहद अहम है। किंग चार्ल्स ने भी अमेरिका में अपने बयानों में नाटो की एकजुटता पर जोर दिया है। ईरान युद्ध के चलते अमेरिका–ब्रिटेन के संबंधों में तनाव पहले टैरिफ युद्ध और अब ईरान युद्ध में शामिल होने से ब्रिटेन के इनकार के चलते अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। ईरान युद्ध में साथ नहीं देने के लिए

ट्रंप कई बार सार्वजनिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की तीखी आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन के संबंध मजबूत करने के लिए ब्रिटिश शाही परिवार का इस्तेमाल ब्रिटेन की पुरानी रणनीति रही है। ट्रंप ऐसे एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें ब्रिटेन ने दो बार राजकीय दौरे का सम्मान दिया है, और वे किंग चार्ल्स के साथ अपनी दोस्ती की खुलकर तारीफ करते हैं। हालांकि सांविधानिक सम्राट होने के नाते किंग चार्ल्स सरकार की आधिकारिक नीति से अलग कोई बयान नहीं दे सकते। ऐसे में अगर ट्रंप, ईरान पर हमले में ब्रिटेन की मदद न मिलने पर फॉकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन करते हैं तो किंग चार्ल्स इस पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन–अमेरिका के संबंधों को बताया सबसे बड़ा गठबंधन ओवल ऑफिस में मुलाकात और कांग्रेस को संबोधित करने के दौरान किंग चार्ल्स ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के गठबंधन को मानव इतिहास के सबसे बड़े गठबंधनों में से एक बताया। उन्होंने यूक्रेन की मदद का भी आह्वान किया और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने की बात कही, जो ट्रंप की प्राथमिकता में बिल्कुल भी नहीं है। शाही दौरे से सुधर सकते हैं दोनों देशों के रिश्ते औपचारिकताओं से परे, यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह दौरा ट्रंप की विदेश नीति को प्रभावित कर पाएगा। यह दौरा दोनों नेताओं के लिए अपनी छवि मजबूत करने का अवसर भी है।

ईरान युद्ध लंबा खिंचने और महंगाई बढ़ने से ट्रंप की लोकप्रियता प्रभावित हो रही है। ऐसे में व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि शाही मुलाकात की तस्वीरें ध्यान भटका सकती हैं। वहीं ब्रिटेन के लिए यह दौरा दिखाता है कि राजशाही आज भी उसकी अहम सॉफ्ट पावर है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त जॉर्ज ब्रैंडिस के अनुसार, किंग चार्ल्स के पास दशकों का अनुभव है, जिससे वे विदेशी नेताओं को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह दौरा राजनीतिक बदलाव लाने में भले सीमित रहे, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में राजशाही की भूमिका अब भी प्रासंगिक है।

`कहीं उन्हें दिल का दौरा न पड़ जाए': ईरान ने यूएस को दी खतरनाक हथियार की धमकी, दोनों देशों में टकराव हुआ तेज

एजेंसी/पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ जारी संघर्ष के बीच एक नए और डर पैदा करने वाले हथियार के इस्तेमाल की खुली चेतावनी दी है। ईरान की खुली धमकी

ईरानी नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि इस्लामिक गणराज्य बहुत जल्द ऐसा हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे दुश्मन बुरी तरह घबरा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह हथियार दुश्मन के बेहद करीब मौजूद है और तंज कसते हुए बोले, उम्मीद है कि उन्हें दिल का दौरा न पड़ जाए। दुश्मन की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही

ईरानी कमांडर ने अमेरिकी रणनीति पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि आर्थिक दबाव और तेल व्यापार को रोककर तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि दुश्मन यह मान बैठे थे कि वे कम समय में अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन अब यही सोच सैन्य अकादमियों में मजाक बन चुकी है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकराया

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के बदले अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को भी टालने का सुझाव शामिल था, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने क्या किया दावा? ईरानी कमांडर ने दावा किया कि ईरानी बलों ने अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन (सीवीएन–72) के खिलाफ कम से कम सात मिसाइल ऑपरेशन अंजाम दिए, जिसके कारण कुछ समय के लिए अमेरिका उस पोत से विमान उड़ाने या हवाई अभियान चलाने में असमर्थ रहा। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका और इस्राइल द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद उसने अब तक 100 से अधिक जवाबी हमले किए हैं, जो पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर केंद्रित थे। जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का कदम उठाया, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम समुद्री मार्ग है और सामान्य समय में दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। होर्मुज को दी चेतावनी ईरान ने दावा किया कि उसने इस जलमार्ग को अरब सागर की ओर से बंद कर दिया है और अब दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ रही है। कमांडर ने चेतावनी दी कि अगर कोई जहाज नजदीक आता है तो तुरंत सैन्य कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नाकेबंदी के बावजूद कुछ जहाज ईरानी बंदरगाहों से निकले हैं और कुछ अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल रहे हैं। ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी कार्रवाई को गैरकानूनी जब्ती बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमेरिकी बलों ने ईरानी जहाजों को कब्जे में लेकर चालक दल और उनके परिवारों को बंधक बना लिया है। उन्होंने इसे न सिर्फ समुद्री डकैती बल्कि बंधक बनाना करार दिया और कहा कि अमेरिकी ताकतें सोमाली समुद्री लुटेरों से भी बदतर हैं, क्योंकि वहां के लुटेरे गरीबी के कारण ऐसा करते थे, जबकि अमेरिका ने इसमें बंधक बनाने जैसे अपराध को भी जोड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में मारे गए लोगों का बदला खून की आखिरी बूंद तक लिया जाएगा और दुश्मनों को ऐसा झटका दिया जाएगा जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहेगा।

ट्रंप ने होर्मुज का नाम बदलकर `ट्रंप जलडमरूमध्य' किया, सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है, जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर ट्रंप जलडमरूमध्य कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साझा एक पोस्ट को री–पोस्ट किया, जिसमें होर्मुज की तस्वीर को ट्रंप जलडमरूमध्य दिखाया गया है। हालांकि जिस यूजर की पोस्ट को ट्रंप ने री–पोस्ट किया है, वह पोस्ट नहीं दिख रही है। पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा है होर्मुज जलडमरूमध्य होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन समुद्री मार्गों में से एक है। इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया का करीब 20–30 प्रतिशत कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान अमेरिका और इस्राइल युद्ध के चलते ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई और दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आया। अब अमेरिका ने भी होर्मुज की नाकाबंदी कर दी है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ने होर्मुज की नाकाबंदी की हुई है अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी की हुई है। ईरान ने समझौते के लिए होर्मुज को खोलने का प्रस्ताव दिया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने होर्मुज की नाकाबंदी को सही बताते हुए कहा कि श्नाकाबंदी, बमबारी से ज्यादा प्रभावी है। ईरान बुरी तरह फंसा हुआ है और उनका दम घुट रहा है। अभी उनकी स्थिति और खराब होगी। ट्रंप का दावा– भारी दबाव में है ईरान की सरकार ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज नाकाबंदी से ईरान पर भारी दबाव पड़ रहा है और वे जल्द से जल्द समझौता करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद कराने की मांग पर अड़े हैं। इससे गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप सरकार का मानना है कि होर्मुज की नाकाबंदी से ईरान तेल की आपूर्ति नहीं कर पाएगा और इससे ईरान अंदरूनी तौर पर कमजोर होगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के ऊर्जा केंद्र बंद होने के कगार पर हैं और तेल निर्यात न कर पाने के कारण ईरान की सरकार भारी दबाव में है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः वोटिंग राइट्स एक्ट कमजोर, ओबामा-हैरिस ने बताया लोकतंत्र के लिए काला दिन

वॉशिंगटन, एजेंसी/अमेरिका में चुनावी कानून को लेकर एक बड़ा और विवादास्पद फैसला सामने आया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लुइसियाना बनाम कैलाइस मामले में 6–3 के बहुमत से ऐसा निर्णय दिया, जिसने वोटिंग राइट्स एक्ट (टत।) की धारा 2 के प्रभाव को काफी हद तक सीमित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब किसी भी चुनावी नक्शे को नस्लीय आधार पर चुनौती देना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। कोर्ट के इस निर्णय ने अमेरिका की राजनीति और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्या है पूरा मामला? इस फैसले को जस्टिस सैमुअल अलिटो ने लिखा। उन्होंने कहा कि अदालत को यह मानकर चलना चाहिए कि राज्य सरकारें सद्भावना में काम कर रही हैं। कोर्ट ने नस्लीय गेरिमैंडरिंग और राजनीतिक गेरिमैंडरिंग के बीच फर्क को और स्पष्ट किया। 2019 के एक फैसले के अनुसार, राजनीतिक आधार पर बनाए गए नक्शों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब नए फैसले के बाद, अगर कोई यह साबित करना चाहता है कि नक्शा नस्लीय भेदभाव के लिए बनाया गया है, तो उसे और अधिक ठोस सबूत पेश करने होंगे। ओबामा और हैरिस की तीखी प्रतिक्रिया

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की कड़ी आलोचना की है, जो मतदान अधिकारों से जुड़ा है। ओबामा ने कहा कि यह फैसला वोटिंग राइट्स एक्ट के एक अहम हिस्से को कमजोर करता है। उनके अनुसार इससे राज्यों को यह मौका मिल सकता है कि वे चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं ऐसे तरीके से बदलें, जिससे काले और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का वोटिंग असर कम हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य इसे राजनीतिक वजह बताकर करें, तो इसे रोकना मुश्किल होगा। ओबामा ने इसे लोकतंत्र के लिए एक झटका बताया, लेकिन लोगों से अपील की कि वे हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट करें और सक्रिय रहें। कमला हैरिस ने इस फैसले को सत्ता हथियाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि कानून की धारा–2 के तहत ब्लैक और ब्राउन वोटर्स को संघीय सुरक्षा मिलती थी। अब भेदभाव रोकने वाला यह प्रावधान कमजोर होगा। उनके अनुसार कुछ राज्य, खासकर दक्षिणी अमेरिका में, जल्द ही चुनावी नक्शे बदल सकते हैं।

सिडनी हमले में 15 मौतों के बाद सख्ती, गन कानून कड़े करने की सिफारिश, क्या अब बदलेगा सुरक्षा ढांचा?

मेलबोर्न , एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय पर हुए भयावह हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था और हथियार कानूनों को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में देश में सख्त

गन कानून सुधार लागू करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट उस दर्दनाक घटना के बाद आई है, जिसमें सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान 15 लोगों की जान चली गई थी। जांच आयोग की बड़ी सिफारिशें रॉयल कमीशन ऑन एंटीसेमिटिज्म एंड सोशल कोहेशन की अध्यक्ष वर्जीनिया बेल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 14 सिफारिशें दी हैं। इनमें से पांच को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में सबसे अहम सिफारिश यह है कि देश में एक समान राष्ट्रीय गन कानून लागू किया जाए और हथियारों की खरीद–बिक्री पर सख्त नियंत्रण हो। क्या था पूरा मामला? बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को हुए इस हमले में पिता–पुत्र साजिद और नवीद अकरम पर आरोप है कि उन्होंने लाइसेंसी हथियारों से भीड़ पर गोलीबारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह हमला इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया गया है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। गन कंट्रोल पर सख्ती की तैयारी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास सीमित संख्या में ही हथियार हों और समय–समय पर लाइसेंस की समीक्षा की जाए। इसके अलावा, सरकार को गन बायबैक योजना शुरू करने की भी सलाह दी गई है, ताकि लोग अपने हथियार वापस जमा कर सकें और बदले में मुआवजा पा सकें। यहूदी समुदाय की सुरक्षा पर फोकस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर इस्राइल–हमास युद्ध के बाद। सरकार ने पहले ही यहूदी समुदाय के धार्मिक स्थलों, स्कूलों और सिनागॉग्स की सुरक्षा के लिए लगभग 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजने कहा कि सरकार सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1996 के ऐतिहासिक गन कानून सुधार के बाद देश अधिक सुरक्षित हुआ है और अब और सख्ती जरूरी है।

13 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को मौत की सजा

एजेंसी/अमेरिका के फ्लोरिडा में लगभग पांच दशक पुराने जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिए गए जेम्स अर्नेस्ट हिचकॉक को आज शाम मौत की सजा दी जाएगी। 70 वर्षीय हिचकॉक को 13 वर्षीय सौतेली भतीजी के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया था। क्या है पूरा मामला? कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, 31 जुलाई 1976 को हिचकॉक अपने भाई के घर में रह रहा था।

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।